उसके बारे में अफसोस का इजहार करना यह मेरा फर्ज बन जाता है । लेकिन उसके साथ-साथ, मेरी आपसे यह दरख्वास्त है...मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन जरूर कीजिए, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है । यह कहना कि साहब, हमारे पीसफुल डिमोनस्ट्रेशन को अगर आप बंद करेंगे तो इसके सिवा हमारे पास रास्ता क्या रह जाता है, तो मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप पीसफुली डिमोनस्ट्रेट करते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, कानून के अंदर अपना काम जब तक करते हैं उस वक्त तक आपको कोई यहां परेशानी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां आप कानून की हद को पार करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद में जो पुलिस आफिसर वहां पर मौजूद होंगे वह अपनी ड्यूटी बजा लाने के लिए काम करेंगे, उनको काम करना पड़ता है और एज होम-मिनिस्टर वह जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आती है । मैं इससे इंकार नहीं कर सकता हूं । मेरी आपसे दरख्वास्त इतनी ही रहेगी कि शान्ति के ढंग से आप जरूर डिमोनस्ट्रेशन कीजिए, जेल भरिए और जो-जो आपको करने की इच्छा है गवर्नमेंट की पालिसी के खिलाफ डिमोनस्ट्रेशन करने के लिए, आपके ऊपर कोई रोकथाम हमने नहीं लगाई है, लेकिन वह कानून के अंदर हों । इसकी अगर आप फिक्र करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के वाकयात फिर हो सकेंगे । मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल : महोदय, मेरा कहना यह है कि होम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही, सही है । लेकिन, लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी ? क्या गिरफ्तारी नहीं की जा सकती थी ? चतुरानन मिश्र जी ने यह सही कहा है कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए था । जब सुबह से यह पता था कि आज यह लोग गिरफ्तारी देने वाले हैं तो गिरफ्तार करना चाहिए था ।...(व्यवधान)... इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, बजाय लाठीचार्ज करते, लाकर पानी छोड़ते या टीयर गैस छोड़ते । उनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए था । यह बहुत ही गलत काम किया है । मैं वाकआउट करता हूं । ...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद सलीम : वहां महिलाओं के सामने मारपीट हुई । शांतिपूर्ण ढंग से डिमोनस्ट्रेशन चल रहा था ।...(व्यवधान)...

(At this stage some Hon. Members left the chamber).

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir. I have an important point to make.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : फिर, किसी दूसरे पर बोल लीजिए ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Just one minute, please.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिए, फिर बात बढ़ जाएगी, जहां से खतम हुई है वहीं से । ...(व्यवधान)...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : I am raising only a question of record. You will agree with me that no matter how bad the Indians may be, you cannot say in this House that the British were better. This is what Mr. Balaram said that it was much better during 1934 when the British were there. Perhaps, the British had a soft corner for the communists, I do not know.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : Please sit down.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: But the Indian Government cannot be considered under any circumstances to be worse than the British Government.

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : गौतम जी, अभी नहीं ।...(व्यवधान)...

THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1993.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) :

Mr. Vice-Chairman Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

As the House is aware, a Committee was set up in December, 1987 to go into the functioning of the various administrative and municipal authorities in Delhi with a view to ensuring efficiency and effectiveness in their functioning. The Committee, popularly known as Balakrishna Committee, submitted its Report after a detailed study of the issues involved and examined the views expressed in various memoranda, reports and other materials. The recommendations made by the Committee regarding the administrative set-up in Delhi were

considered, and necessary legislation including the Constitutional amendment to provide for the establishment of a Legislative Assembly and a Council of Ministers for the National Capital Territory of Delhi has already been enacted.

The recommendations made by the Committee regarding the municipal setup were examined. The provisions of the Constitution (74th Amendment) Act, 1992 relating to 'Municipalities' were also taken into account and the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1993 was passed by Lok Sabha on 4-8-1993.

The Bill envisages decentralisation of Municipal services by establishing Wards Committees having adequate powers including the power to sanction plans and estimates for the municipal works costing up to Rs. One Crore subject to the budgetary provision. These Committees, being more resoonsive to the public, are expected to facilitate expeditious redressal of their grievances.

The provisions of the Bill explain in detail the charges which are sought to be made. I do not think I should trouble the Hon. Members with more details of this Bill.

I have no doubt that this Bill will go a long way to satisfy the demands of the residents of Delhi for better municipal administration.

With these words, Sir, I commend this Bill to this House for approval.

The question was proposed.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहब, मैं बहुत मख्मसे में हूं । यह बिल बुनियादी तौर पर मैं बहुत ही इसको कमजोर बिल मानता हूं । दिल्ली वालों की जरूरत को पूरा करने का कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बिल का । मख्मासा मेरा यह है कि मैं यह भी चाहता हूं कि चनाव न रोके जाएं इसलिए इस दुविधा के बीच में मैं अपनी बात कह रहा हूं । मैं बिल की उन खास मदों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जिसके मुताल्लिक मुझे बुनियादी शिकायतें हैं । लेकिन इससे पहले मैं वहां शाऊं, यह बिल किस जहनियत की पदावार है, उसका जिक्र करना चाहता हूं । मैं इसका जिक्र एक दफे होम मिनिस्टर की खिदमत में कर चुका हूं । मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूं, अब भी नहीं करूंगा । लेकिन मेरी शिकायत बड़ी शिद्दत से है कि 37 साल में इस मुल्क की जो जहनियत बना ली गई है और जिसके आधार पर तमाम दलीलें इस बिल के लिए दी जा रही हैं, उस जहनियत का नतीजा सिर्फ एक निकला है कि बेरहमी के साथ दिल्ली वालों को फैंचाइज के हक से जुदा रखा गया है । कभी उनका फ्रैंचाइज ले लिया गया है और कभी कुछ हिस्सों में लिया गया है और एक ऐसी अजीबोगरीब जहनियत पैदा कर दी गई है कि जब कभी भी इस किस्म का बिल आता है, चाहे वह असेंबली के संबंध में हो या कारपोरेशन के संबंध में हो, तो सादा होता है, जो दिल्ली वालों के लिए कुछ मांगना चाहते हैं, वह यह सोचते हैं कि सरकार इतना दे देगी, इतना मांगलो । जहां तक सरकार का और यह ब्यूरोक्रेटिक जो क्रेकिट है उस क्रेकिट ने तो यह जहन बना लिया है कि दिल्ली वालों की गर्दन ब्यूरोक्रेसी तथा हिन्दुस्तान के राजनीतिक शासकों के हाथ में रहनी चाहिए । अब यह जहनियत मेरी समझ में नहीं आई, नाम बदल दिया गया है दिल्ली स्टेट का । कल तक यह दिल्ली स्टेट थी, आज यह केपिटल टेरिटोरी ही कहलाती है । आप जरा गौर तो करें कि आपने क्या-क्या किया है इस दिल्ली के साथ । एक दफे कुछ आधी, पौनी सी असेंबली आई थी, पूरी नहीं आई थी उस दिन के बाद और उसके बाद मैट्रोपालिटिन कौंसिल आई ।

Metropolitan Council was nothing but a debating society.

इतनी मजहकाखेज थी वह कि यहां पार्लियामेंट में बजट पास हो जाता था और पास हो जाने के बाद मेट्रोपालिटिन कौंसिल में उस पर बहस होती । कोई अख्त्यारात नहीं थे । तो मेरा कहना यह है सदर साहब, यह जो बिल लाए हैं इससे दिल्ली वालों की जरूरत को पूरा होने का क्या तरीका बनता है । बिल्कुल उस पुरानी जहनियत का नतीजा है यह बिल कि हम यह देंगे या नहीं देंगे । जिस चीज के लिए मैंने होम मिनिस्टर साहब से क्षमा मांगी थी मैं उसके लिए यह कहना चाहता हूं कि मैंने आपका बयान पढ़ा भी है और सुना भी है, उसका लबोलहजा ही ऐसा है । यह नहीं लगता है कि यहां पोलिटिकल एक्टिविटी के प्रोडक्टिव तजवीज है यह जिद और यह लगता है कि यह हम दे देंगे और यह नहीं देंगे और किस्सा खत्म । यह लबोलहजा इतना मुखतलिफ है, क्षमा करेंगे आप मुझे, बिल्कुल बहुत गलत लबोलहजे की बात है । मैं तो यह सबका सब लेकर आया हूं, जब बिल्डिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा तो बताऊंगा कि आपने क्या कहा है, आपने सर्विसेज के बारे में क्या कहा है, आपने दिल्ली के कारपोरेशन के चुने हुए मेंबर्स के बारे में क्या कह दिया है कि हम उनको अख्त्यारात यहां के लोगों के चुने जाने के लिए । मुझे ताज्जुब होता है कि यह भाषा कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है

This is because of the fact that these officers, who" are being appointed there should not come directly or indirectly

under the influence of the elected Members. They should continue *to* be under your influence, but not under the influence of the elected Members. Elected Members are not going to be given any right to appoint Officers who are going to serve in the Corporation under them.

इस किस्म की दर्जनों जगा बातें है।

सदर साहब, यहां पर कौके हुकूमत खत्म होकर पहले इस सरकार को यह तस्लीम करना चाहिए कि दिल्ली वालों के जम्हूरी हक्क क्या हैं, उनके जम्हूरी हक्क उनको क्यों नहीं मिलते हैं ? एक अजीबो-गरीब बात है। मिसाल वाशिंगटन की कोट की गई है कि एक जगह पर दो सरकारें नहीं रह सकती। केन्द्रीय सरकार का हिन्दुस्तान की हर प्रान्तीय सरकार से एक रिश्ता है। केन्द्रीय सरकार का दिल्ली स्टेट की सरकार से भी वही रिश्ता होना चाहिए। इसलिए दलील के कोई मायने नहीं है, बिलकुल बेमानी दलील है। इसलिए जो ताकतें आपको यहां की एसेंब्ली को देनी है, कारपोरेशन को देनी चाहिए, भरपूर देनी चाहिए। उसके अंदर ऐहकामात जारी करना और यहां कौके हुकूमत का इजहार करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली के डेमोक्रेटिक राइट्स पर पाबंदी पहले भी थी, आज भी है। दो गवर्नमेंट्स की लॉजिक का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली एक स्टेट थी, एक स्टेट है और एक स्टेट रहनी चाहिए और भरपूर अख्तियारात यहां की एसेंब्ली को होने चाहिए और सिविल अख्तियारात भी भरपूर होनी चाहिए। मैं कुछ चीजें बीच में छोड़ रहा हूं, मुझे मालूम नहीं था, मैं बिलकुल मजबूर हूं कि वक्त की इतनी तंगी है। मेरी मौजूदगी में ही इस का डेढ़ घंटा तय हुआ था।

आपने कभी गौर किया कि दिल्ली का एक इलेक्टोरेल कालेज था, वह इलेक्टोरेल कालेज राज्य सभा का मेंबर चुनता था, वह इलेक्टोरेल कालेज राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता था, यह इलेक्टोरेल कालेज उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता था। कितने अरसे से दिल्ली वाले राज्य सभा में नुमाइंदगी नहीं कर सके। कितने अरसे से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके। यह किस किस्म की जम्हूरियत का चेहरा है ?

सदर साहब, मैं इसकी बजाजेब में आने से पहले आपके बयान में एक जिक्र आया है दिल्ली की वैल्यूएबल लैंड्स का और जाहिर है कि लैंड का कुछ न कुछ संबंध दिल्ली की कारपोरेशन से भी है। कभी भी सदर साहब इस सरकार ने गौर किया कि दिल्ली में लैंड से डील करने वाली अथारिटीज कितनी हैं ? मल्टीप्लिसिटी आफ अथारिटी है। और लुत्फ यह है कि कोई अथारिटी नहीं जानती कि उसके फंक्शंस का डिमार्केशन कहां खत्म होता है। डी० डी० ए० जिससे डील करता है, दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन जिससे डील करता है, आपका मिनिस्ट्री आफ अरबन डेवलपमेंट है, एल० एन० डी० ओ० आफिस है, बिलकुल एकदम उधम मचा हुआ है। उसके बाद आपने अपने बयान में जिक्र ऐनक्रोचमेंट का किया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कौन सी जमीनों पर ऐनक्रोचमेंट है ? कौन से सन से दिल्ली की तमाम जमीनें सेक्शन 4 के मातहत नोटिफाई कर दी गई है ? आज सरकार को जरूरत है जमीन की या नहीं, लेकिन तमाम की तमाम जमीनें सेक्शन 4 के मातहत नोटिफाई की गई हैं। जिस समय जरूरत होती है तो सेक्शन 6 के मातहत उनको ऐक्वायर किया जाता है। जब आप ऐक्वायर करते हैं सेक्शन 4 के मातहत, नोटिफिकेशन के बाद चाहे 30 वर्षों के बाद उसको ऐक्वायर करें, लेकिन आप जिस वक्त जमीन का कंपेंसेशन देते हैं वह उस वक्त का देते हैं जिस वक्त सेक्शन 4 के मातहत आपने एक्वायर किया। ऐनक्रोचमेंट का तमाशा आपका यह दिल्ली में ऊधम मचा रहा है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऐनक्रोच्ड लैंड को खाली कराना चाह रहा है। मैं पहले भी पूछ चुका हूं होम मिनिस्टर साहब से, ऐनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, दिल्ली की जमीनें बाकई कीमती है, उनका ख्याल रखना चाहिए लेकिन यह मैं जानना चाहता हूं कि एनक्रोचमेंट के लिए जिस दिन पहली ईंट रखी जाती है उसी दिन ऐनक्रोचमेंट क्यों नहीं रोका जाता है ? जब लाल किला बनकर खड़ा हो जाता है तब जागती है सरकार कि ऐनक्रोचमेंट हो रहा है और आपको मालूम है किस तरह से नेशनल लॉस होता है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिन कर्मचारियों के जरिए से आप हिन्दुस्तान में सरकार चलाने का कारोबार चला रहे हैं, उस किले के ढांचे को खड़े होने में कितना वक्त लगता है और उसमें इन कर्मचारियों का कितना हाथ होता है ?

जब भरपूर मकानात बन जाते हैं उस ऐनक्रोचमेंट को गिराने में राष्ट्रीय लौस, नेशनल लौस कितना होता है, क्या इस पर कभी गौर किया है ? किसी ने गौर नहीं किया। आपने वेल्यूएबल लैण्ड की बात की है। सरकार ने तो एक दफा इन लैण्ड्स को इतना वेल्यूएबल न बन जाय, ये जमीनें लोगों की खरीद से बाहर हो जाये उसको रोकने के लिए एक सिस्टम निकाला था। इस सवाल को लेकर मैं कारपोरेशन तक पहुंच रहा हूं। हिन्दुस्तान में लीज सिस्टम लेकर आप आए थे, सरकार लेकर आई कि इसमें जमीनों को कीमत पर काबू किया जाय। लेकिन जमीनों की कीमत पर काबू नहीं किया गया और 1977 की सरकार ने यह फैसला किया था कि चूंकि लीज सिस्टम अपने मकसद में नाकामयाब

हो चुका है, इसलिए इस सिस्टम को स्क्रैप कर देना चाहिए । फैसला हो गया । मुझे मालूम नहीं वह कौन-सी फायलों में कहां पड़ा हुआ है । आज जिक्र हो रहा है कंवर्शन चार्जेज का । क्या मतलब है कंवर्शन चार्जेज का ? लीज सिस्टम और वैल्यूएबल लैण्ड की बात भी कर रहा हूं, दोनों बातें कर रहा हूं कि अगर इन लैण्ड को वैल्यूएबल नहीं होना चाहिए था । इन लैण्ड की कीमतों को आर्डिनरी सतह तक रहना चाहिए था... (समय की घंटी) ।

अभी से छिड़ गई घंटी तुम्हारी ।

†[شری سکندر بخت ''مدھیہ پردیش''

صدر صاحب، میں بہت مختصر میں ہوں۔ یہ بل بنیادی طور پر میں بہت ہی اس کو کمزور بل مانتا ہوں۔ دلی والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہیں اس بل کا۔ مختصر میرا یہ ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چناؤ روکے نہ جائیں اس لئے اس دوپدھا کے بیچ میں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں بل کی ان خاص مدوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہونگا۔ جس کے متعلق مجھے بنیادی شکایتیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں وہاں آؤں۔ یہ بل کس ذہنیت کی پیداوار ہے۔ اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کا ذکر ایک دفعہ ہوم منسٹر کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ میں سخت الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اب بھی نہیں کروں گا۔ لیکن میری شکایت بڑی شدت سے یہ ہے کہ ۳۷ سال میں اس ملک کی جو ذہنیت بنالی گی ہے اور جس کے آدھار پر تمام دلیلیں اس بل کے لئے دی جارہی ہیں۔ اس ذہنیت کا نتیجہ صرف ایک نکلا ہے کہ بے رحمی کے ساتھ دلی والوں کے فریڈچائز کے حق سے جدا رکھا گیا ہے، کبھی انکا فریڈچائز لے لیا ہے اور کبھی کچھ حصوں میں لیا گیا ہے اور ایک اسی عجیب و غریب ذہنیت پیدا کر دی گی ہے کہ جب کبھی بھی اس قسم کا بل آتا ہے۔ چاہے وہ اسمبلی کے سمبندھ میں ہو یا کارپوریشن کے سمبندھ میں ہو۔ تو سادہ ہوتا ہے۔ جو دلی والوں کے لئے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ سرکار اتنا دے دیگی اتنا مانگ لو۔ جہاں تک سرکار کا اور یہ پیوروکریٹس جو بریکٹ ہیں اس بریکٹ نے تو یہ ذہن بنا لیا ہے کہ دلی والوں کی گردن بیوروکریسی نتھا ہندوستان کے راج نیتیک شاسکوں کے ہاتھ میں رہنی چاہیئے۔ اب یہ ذہنیت میری سمجھ میں نہیں آئی نام بدل دیا گیا ہے دلی اسٹیٹ کا۔ کل تک یہ دلی اسٹیٹ تھی۔ آج یہ کیپیٹل ٹیریٹوری ہی کہلاتی ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ آپ نے کیا کیا کیا ہے اس دلی کے ساتھ۔ ایک دفعہ کچھ آدھی۔ پونی سی اسمبلی آئی تھی پوری نہیں آئی تھی۔ اس دن کے بعد اور اس کے بعد میٹروپولیٹن کاؤنسل آئی۔]

Metropolitan Council was nothing but a debating society.

اتنی مضحکہ خیز تھی کہ یہاں پارلیمنٹ میں بجٹ پاس ہوتا تھا اور پاس ہو جانے کے بعد میٹروپولیٹن کاؤنسل میں اس پر

†[ ] Transliteration In Arabic Script, 21—106 RSS/ND/94.

This is because of the fact that then officers, who are being appointed there should not come directly or indirectly under the influence of the elected Members. They should continue to be under your influence, but not under the influence of the elected Members. Elected Members are not going to be given any right to appoint Officers, who are *going* to serve in the Corporation under them.

اِس قسم کی درجنوں جگہہ باتیں ہیں۔
صدر صاحب۔ یہاں پر شوق حکومت ختم ہوکر اس سرکار کو پہلے یہ تسلیم کرنا چاہیئے کہ دلّی والوں کے جمہوری حقوق کیا ہیں۔ ان کے جمہوری حقوق ان کو کیوں نہیں ملتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ مثال واشنگٹن کی کوٹ کی گئی ہے کہ ایک جگہہ دو سرکاریں نہیں رہ سکتیں۔ کیندریہ سرکار کا ہندوستان کی ہر پرانتیئے سرکار سے ایک رشتہ ہے۔ کیندریہ سرکار کا دلّی اسٹیٹ کی سرکار سے بھی وہ ہی رشتہ ہونا چاہیئے اس لئے دلیل کے کوئی معنی نہیں ہیں بالکل بے معنی دلیل ہے۔ اس لئے جو طاقتیں آپکو یہاں کی اسمبلی کی دیتی ہیں۔ کارپوریشن کو دینی چاہیئے۔ بھرپور دینی چاہیئے۔ اس کے اندر احکامات جاری کرنا اور یہاں شوق حکومت کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیئے۔
دلّی کے ڈیموکریٹک رائٹس پر پابندی پہلے بھی تھی۔ آج بھی ہے۔ دو گورنمنٹس کی لاجک کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دلّی ایک اسٹیٹ تھی۔ ایک اسٹیٹ ہے اور ایک بحث ہوتی تھی۔ کوئی اختیارات نہیں تھے۔ تو میرا کہنا یہ ہے صدر صاحب۔ یہ جو بل لائے ہیں۔ اس سے دلّی والوں کی ضرورت کو پورا ہونے کا کیا طریقہ بنتا ہے۔ بالکل اس پرانی ذہنیت کا نتیجہ ہے یہ بل کہ ہم یہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جس چیز کیلئے میں نے ہوم منسٹر صاحب سے چھما مانگی تھی۔ میں اس کے لئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپکا بیان پڑھا بھی ہے اور سُنا بھی ہے اس کا لب و لہجہ ایسا ہے۔ یہ نہیں لگتا کہ یہاں پالیٹیکل ایکٹی وٹی کے پروڈکٹو تجویز ہے یہ بل اور یہ لگتا ہے کہ ہم یہ دے دیں گے اور یہ نہیں دیں گے اور قصّہ ختم۔ یہ لب و لہجہ اتنا مختلف ہے سمجھا کریں گے آپ مجھے۔ بالکل بہت غلط لب و لہجہ کی بات ہے۔ میں تو وہ سب کا سب لیکر آیا ہوں۔ جب بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں بات کروں گا تو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ نے سروسز کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آپ نے دلّی کے کارپوریشن کے چنے ہوئے ممبرس کے بارے میں کیا کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو اختیارات یہاں کے لوگوں کے چنے جانے کے لئے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ بھاشا کوئی ایسے استعمال کر سکتا ہے۔

یہ ہے کہ کوئی اتھارٹی نہیں جانتی کہ اس کے فنکشن کا ڈی مارکیشن کہاں ختم ہوتا ہے ڈی۔ڈی۔اے۔جس سے ڈیل کرتا ہے۔دلّی ایڈمنسٹریشن جس سے ڈیل کرتا ہے۔آپ کا منسٹری آف اربن ڈیولپمنٹ ہے۔ایل این ڈی او آفس ہے۔بالکل ایک دم اودھم مچا ہوا ہے۔اس کے بعد آپ نے اپنے بیان میں ذکر اینکروچمنٹ کا کیا ہے۔کیا آپنے کبھی غور کیا ہے کہ کونسی زمینوں پر اینکروچمنٹ ہے۔کون سے سنہ سے دلّی کی تمام زمینیں سیکشن ۴ کے تحت نوٹیفائی کر دی گئی ہیں۔آج سرکار کو ضرورت ہے زمین کی یا نہیں۔لیکن تمام کی تمام زمینیں سیکشن ۴ کے ماتحت نوٹیفائی کی گئی ہیں۔جس سے ضرورت ہوتی ہے تو سیکشن ۴ کے ماتحت نوٹیفکیشن کے بعد چاہے ۲۰ برسوں کے بعد اس کو ایکوائر کریں لیکن آپ جس وقت زمین کا کمپنسیشن دیتے ہیں۔وہ اس وقت کا دیتے ہیں جس وقت سیکشن ۴ کے ماتحت آپ نے ایکوائر کیا۔اینکروچمنٹ کا تماشہ آپ کا یہ دلّی میں اودھم مچا رہا ہے میونسپل کارپوریشن اینکروچڈ لینڈ کو خالی کرانا چاہ رہا ہے۔میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں۔ہوم منسٹر صاحب سے۔اینکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیئے۔دلّی کی زمینیں واقعی قیمتی ہیں اسٹیٹ رہنی چاہیئے اور پورے اختیارات یہاں کی اسمبلی کو ہونے چاہئیں اور رسول اختیارات بھی بھرپور ہونی چاہیئے۔میں کچھ چیزیں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں۔مجھے معلوم نہیں تھا۔میں بالکل مجبور ہوں کہ وقت کی اتنی تنگی ہے۔میری موجودگی میں ہی اس کا ڈیڑھ گھنٹہ طے ہوا تھا۔

آپ نے کبھی غور کیا کہ دلّی کا ایک الیکٹوریل کالج تھا۔وہ الیکٹوریل کالج راجیہ سبھا کا ممبر چنتا تھا۔وہ الیکٹوریل کالج راشٹرپتی کے چناؤ میں حصّہ لیتا تھا وہ الیکٹوریل کالج اب راشٹرپتی کے چناؤ میں حصّہ لیتا تھا۔کتنے عرصے سے دلّی والے راجیہ سبھا میں نمائندگی نہیں کر سکے۔کتنے عرصے سے راشٹرپتی اور اب راشٹرپتی کے چناؤ میں حصّہ نہیں لے سکے۔یہ کس قسم کی جمہوریت کا چہرہ ہے۔

صدر صاحب۔میں اس کی کلاریفیکیشن آنے سے پہلے آپکے بیان میں ایک ذکر آیا ہے دلّی کی ویلیو ایبل لینڈس کا اور ظاہر ہے کہ لینڈ کا کچھ نہ کچھ سمبندھ دلّی کی کارپوریشن سے بھی ہے کبھی بھی صدر صاحب اس سرکار نے غور کیا دلّی میں لینڈ سے ڈیل کرنے والی اتھارٹیز کتنی ہیں۔ملٹی پلسٹی آف اتھارٹی ہے۔اور لطف

کیا جائے لیکن زمینوں کی قیمت پر قابو نہیں کیا گیا۔ اور ۱۹۷۷ء کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ لیز سسٹم اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو چکا ہے۔ اس لئے اس سسٹم کو اسکریپ کر دینا چاہیئے۔ فیصلہ ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سی فائلوں میں کہاں پڑا ہوا ہے۔ آج ذکر ہو رہا ہے کنورشن چارجز کا۔ کیا مطلب ہے۔ کنورشن چارجز کا۔ لیز سسٹم اور ویلیو بل لینڈ کی بات بھی کر رہا ہوں۔ دونوں باتیں کر رہا ہوں کہ اگر ان لینڈ کو ویلیو ایبل نہیں ہونا چاہیئے تھا ان لینڈ کی قیمتوں کو آرڈنری سطح تک رہنا چاہیئے تھا..." وقت کی گھنٹی"...

ابھی سے چھڑ گئی گھنٹی تمہاری۔

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ऐसा है कि डेढ़ घंटा आप लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसके लिए मुकर्रर किया है और सब पार्टियों का उनके हिसाब से समय निर्धारित है, जैसे आपके 11 मिनट हैं। दूसरे का 10 मिनट और किसी का 5 मिनट। मैं अपनी ओर से जो यहां लिखा है, जब समय खत्म होगा, घंटी बजाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि आप खत्म कर दें। आप अपनी बात पूरी कहें, लेकिन मेरा यह कहना है कि मैं अपने फर्ज की अदायगी करूंगा ताकि कम से कम उस दल को और उस वक्ता को पता चल जाय कि हमारा वक्त इतना था, मैंने यह किया और अब हमको इतनी देर तक और बोल कर अपनी बात खत्म करनी है।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं लीज की बात कर रहा था। लीज के सिस्टम में कंवर्शन चार्जेज मांगने का आपका क्या हक है? लीज का सिस्टम सिर्फ जमीनों की कीमतों को काबू करने के लिए लाये गये थे और वह तो आप

†[ITransliteration in Arabic Script.

ان کا خیال رکھنا چاہیئے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اینکروچمنٹ کے لئے جس دن پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے اسی دن اینکروچمنٹ کیوں نہیں روکا جاتا ہے۔ جب لال قلعہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تب جاگتی ہے سرکار کہ اینکروچمنٹ ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کس طرح سے نیشنل لاس ہوتا ہے آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جن کرپچاریوں کے ذریعہ سے آپ ہندوستان میں سرکار چلانے کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ اس قلعہ کے ڈھانچے کو کھڑے ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس میں ان کرپچاریوں کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے۔

جب بھرپور مکانات بن جاتے ہیں اس اینکروچمنٹ کو گرانے میں راشٹریہ لاس۔ نیشنل لاس کتنا ہوتا ہے۔ کیا اس پر کبھی غور کیا ہے کسی نے غور نہیں کیا۔ آپ نے ویلیو بل لینڈ کی بات کی ہے سرکار نے تو ایک دفعہ ان لینڈس کو اتنا ویلیو بل نہ بن جائیے۔ یہ زمینیں لوگوں کی خرید سے باہر نہ ہو جائیں۔ اس کو روکنے کے لئے ایک سسٹم نکالا تھا۔ اس سوال کو لے کر میں کارپوریشن تک پہنچ رہا ہوں۔ ہندوستان میں لیز سسٹم سے کر آپ آئے تھے۔ سرکار نے کہ آئی کہ اس میں زمینوں کی قیمت پر قابو

रख नहीं सके और आपने उसको रेवेन्यू अर्निंग सिस्टम बना दिया । फैसला अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की फायलों में मौजूद है । केबिनट नोट बनाने के उसमें हुक्म हैं कि आप ढाई सौ, तीन सौ गज के प्लॉट से कम से कम लीज सिस्टम को खत्म करने की इब्तदा करें । न आप जमीनों पर काबू कर सके और उल्टा जिस मकसद के लिए लीज सिस्टम को लेकर आये थे, आपने लोगों पर बोझ डालना शुरू कर दिया और लोग इतने मजबूर हैं कि आपके सामने सिर झुकाने पर आपसे सौदा कर रहे हैं । इस चीज का सौदा कर रहे हैं कि इतने साल की लीज दे दीजिए । बिलकुल नहीं देना चाहिए । आपने वैल्युएबल लैण्ड का जिक्र किया था, एनक्रोचमेंट की बात कही थी । अब चूंकि सदर साहब ने करीबन धमका दिया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने गौर फरमाया है कि सिविक बोडी किस का नाम है । आपने तमाम ताकतें उससे ले ली हैं । आप चुने हुए लोगों को ताकत देना क्या चाहते हैं ? इस कारपोरेशन का वाकई क्या मकसद होगा, क्या आपने इस पर गौर फरमाया है ? दुनिया भर की ताकतें आपने उनके हाथ से ले ली । बिल्डिंग बाई लाज अगर दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन नहीं बनाएगी तो क्या सेन्टर में बैठे हुए लोग बनाएंगे ? मुझे अफसोस है कि जगह-जगह आपके बयान में होम मिनिस्टर साहब, यह आया है कि क्योंकि यहां की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत नाकाम हो गई है और नाकाम रही है, इसलिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को बहुत भारी ताकतें अपने हाथ में लेनी पड़ी हैं । कितने ही अर्से से यहां कारपोरेशन नहीं है । कितने ही अर्से से यहां सरकार नहीं है । बराहेरास्त तमाम मामलात मरकजी सरकार के हाथ में है । मैं जानना चाहता हूं कि मरकजी सरकार में जब से मामलात आपके हाथ में हैं, क्या कमाल दिखाया है हिन्दुस्तान में । बिजली नहीं, पानी नहीं । बारिश जो जाय तो वाटर लोगिंग जिसमें बसें सब डूब जाती हैं । आपकी सरकार ने क्या किया ? जो लोग कल चुने जाने वाले हैं आप अभी से प्रजूम करके जानना चाहते हैं । यह तो आपकी कोताहियों का जिक्र है । वे लोग तो अभी चुने भी नहीं गये हैं । जब चुने जायें और वे अपने काम को अंजाम न दे सकें तब कुछ कहें तो बेहतर है । सीवरेज की जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले ली है । गली कूंचों की सफाई की जिम्मेदारी भी है । वे म्युनिसिपल काउंसिलर क्या करेंगे । सीवरेज, ड्रेनेज की सफाई कौन करेगा ! कमाल हो गया है, ऐसी कुछ एजीबो गरीब तकसीम की है कि बिजली की जिम्मेदारी आपने ले ली, वाटर सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी आपने अपने हाथ में ले ली । फायर सर्विस का सवाल है, मरने-जीने का सवाल है, सीवरेज का भी है, अस्पताल का मामला है । म्युनिसिपल कारपोरेशन को अस्पताल या क्लिनिक बनाने की इजाजत क्यों नहीं है ? आप जानते हैं कि इस वक्त मेडिकल सर्विसेज की किस बला की कमी है दिल्ली के अन्दर । म्युनिसिपल कारपोरेशन जगह-जगह, छोटी-छोटी कालोनीज में छोटे-छोटे अस्पताल छोटे-छोटे क्लिनिक कायम कर सकती है लेकिन उसका अख्तियार आपने ले लिया है । सेहत का मामला आपके हाथ में है । बिजली का मामला आपके हाथ में है । वाटर-सीवेज का मामला आपके हाथ में है । लोगों को अप्वाइंट करने का मामला आपके हाथ में है । बिल्डिंग बाई-लाज का क्या ताल्लुक है । मकानात का बनाना, निर्माण होना बराहेरास्त सिविक बॉडीज का काम है, बिल्डिंग बाई-लाज बनाने के लिए आपने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है । माफ करेंगे, आपका जो यह बिल है यह कतई तौर पर एंटी डेमोक्रेटिक है । बुनियादी तौर पर उस जहनियत से मिला हुआ है, जिस जहनियत के मातहत आप दिल्ली वालों को जम्हूरी हकूक किसी न किसी ढंग से देने में रुकावट डालते रहे हैं । शुक्रिया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपको मैंने नहीं रोका ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने यह अर्ज किया था जिस वक्त आप घंटी बजाएंगे मैं बैठ जाऊंगा । तो सदर साहब मेरा कहना यह है कि यह कारपोरेशन लूली-लंगड़ी भी नहीं है, इसको आप बैसाखियां लगा कर भी नहीं चला सकते हैं । चुने हुए लोगों का एक कमाल जरूर होता है कि आप लाख गालियां दे दीजिए कि तुम चुने हुए लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम उस कारपोरेशन में अपनी अर्जी के लोगों को मुलाजिम रख सको क्योंकि तुम करप्ट हो मगर यह कारपोरेशन के मेम्बर जो होंगे इस तक लोगों की आवाज तो पहुंच जाती है । अपनी आवाज नार्थ ब्लाक तक कैसे पहुंचाएगा दिल्ली वाला, कोई नहीं पहुंचा सकता है । जो आज छोटी छोटी खिदमत करने वाले हैं, वो चुन

वाले हैं, मेरी आप से दरख्वास्त है मोदेबाना कि आप दिल्ली वालों को खुले दिल से जम्हूरी हकूक दीजिए। खींच तान कर मत दीजिए कि जैसे पतंग को कभी ढील दे दिया, कभी खींच लिया, भरपूर अख्तियारात दीजिए। मैं समझता हूं जिस किस्म का निकम्मा कारोबार अब तक चलता रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट तो होगी ही होगी क्योंकि चुने हुए लोगों का बराहेरास्त आवाम में बराहेरास्त जनता से ताल्लुक होगा। यह बिल दिल्ली वालों की खिदमत के काबिल नहीं है। यह बिल लूला-लंगड़ा बिल तक नहीं है, लंगड़ा-लूला घिसट तो लेता है लेकिन इसमें तो घिसटने की भी गुंजाइश नहीं है। मैं जानता नहीं, आप लोक सभा से यह बिल पास कराके ला चुके हैं तो मेरे यहां कहने का मकसद क्या हो सकता है ? क्या इसके अन्दर कोई तबदीली मुमकिन हो सकती है जो आप लाएं। आपने गर्दन हिला दी। आपके गर्दन हिलाने से पहले ही मैं जानता था। इसलिए मेरे यहां बोलने का मकसद क्या हो सकता है, मैं व्यर्थ बोल रहा था। मेरी आवाज़ तो ऐसी है जैसे अकेला कोई सेहरा में गूंज है, इसके इलावा कुछ भी नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं। दिल्ली वालों के जम्हूरी हकूक छीनने का किसी को भी कोई हक नहीं है। 47 सालों से यह कहानी बराबर चल रही है, उसमें थोड़ा सा वकफा हमारी गुनहगारी का भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब आपका।

شری سکندر بخت: میں لیز کی بات کر رہا تھا۔ لیز کے سسٹم میں کمنوریشن چارجز مانگنے کا آپ کا کیا حق ہے۔ لیز کا سسٹم صرف زمینوں کی قیمتوں کو قابو کرنے کیلئے لائے گئے تھے۔ اور وہ تو آپ دیکھ نہیں سکے اور آپ نے اس کو ریویجیوارنگ سسٹم بنا دیا۔ فیصلہ اربن ڈیولپمنٹ منسٹری کی فائلوں میں موجود ہے۔ کیبنٹ نوٹ بنانے کے اس میں حکم ہیں کہ آپ ڈھائی سو تین سو گز کے پلاٹ سے کم سے کم لیز سسٹم کو ختم کرنے کی ابتدا کریں۔ نہ آپ زمینوں پر قابو کر سکے اور الٹا جس مقصد کے لئے لیز سسٹم کو لے کر آئے تھے آپ نے لوگوں پر بوجھ ڈالنا شروع کر دیا اور لوگ اتنے مجبور ہیں کہ آپکے سامنے سر جھکانے پر آپسے سودا کر رہے ہیں اس چیز کا سودا کر رہے ہیں کہ اتنے سال کی لیز دے دیجئے بالکل نہیں دینا چاہیئے آپ نے ویلیو ایبل لینڈ کا ذکر کیا تھا۔ اینکروچمنٹ کی بات کہی تھی۔ اب چونکہ صدر صاحب نے قریباً دھمکا دیا ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غور فرمایا ہے۔ کہ سوک باڈی کس کا نام ہے۔ آپ نے تمام طاقتیں اس سے لے لی ہیں۔ آپ چنے ہوئے لوگوں کو طاقت دینا کیا چاہتے ہیں۔ اس کارپوریشن کا واقعی مقصد کیا ہوگا۔ کیا آپ نے اس پر غور فرمایا ہے۔ دنیا بھر کی طاقتیں آپ نے ان کے ہاتھ سے لے لی۔ بلڈنگ بائی لاز اگر دلی میونسپل کارپوریشن نہیں بنائے گی تو کیا سنٹر میں بیٹھے ہوئے لوگ بنائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ جگہ جگہ آپ کے بیان میں ہوم منسٹر صاحب یہ آیا ہے کہ کیوں کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن بہت ناکام ہو گئی ہے اور ناکام رہی ہے

ہاتھ میں ہے لی۔ فائر سروس کا سوال ہے۔ مرنے جینے کا سوال ہے۔ سیوریج کا بھی ہے۔ اسپتال کا معاملہ ہے۔ میونسپل کارپوریشن کو اسپتال یا کلینک بنانے کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میڈیکل سروسز کی کس بلا کی کمی ہے دلّی کے اندر۔ میونسپل کارپوریشن جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی کالونیز میں چھوٹے چھوٹے اسپتال، چھوٹے چھوٹے کلنک قائم کر سکتی ہے لیکن اس کا اختیار آپ نے لے لیا ہے۔ صحت کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے بجلی کا معاملہ آپکے ہاتھ میں ہے واٹر سیوریج کا معاملہ آپکے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کو اپائنٹ کرنے کا معاملہ آپکے ہاتھ میں ہے بلڈنگ بائی لاز کا کیا تعلق ہے۔ مکانات بنانا۔ زمان ہونا براہ راست سوک باڈیز کا کام ہے بلڈنگ بائی لاز بنانے کے لئے آپنے ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ معاف کریں گے۔ آپ جو یہ بل ہے یہ قطعی طور پر انٹی ڈیموکریٹک ہے۔ بنیادی طور پر اس ذہنیت سے ملا ہوا ہے۔ جس ذہنیت کے ماتحت آپ دلّی والوں کو جمہوری حقوق کبھی نہ کسی ڈھنگ سے دینے میں رکاوٹ ڈالتے رہے ہیں۔ شکریہ

اس لئے سنٹرل گورنمنٹ کہ بہت بھاری ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لینی پڑی ہیں کتنے ہی عرصے سے یہاں کارپوریشن نہیں ہے کتنے ہی عرصے سے یہاں سرکار نہیں ہے براہ راست تمام معاملات مرکزی سرکار کے ہاتھ میں ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار میں جب سے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں کیا کمال دکھایا ہے ہندوستان میں۔ بجلی نہیں۔ پانی نہیں۔ بارش ہو جاتے تو واٹر لوگنگ جس میں بسیں ڈوب جاتی ہیں۔ آپ کی سرکار نے کیا کیا۔ جو لوگ کل چنے جانے والے ہیں۔ آپ ابھی سے پرزیوم کر کے جاننا چاہتے ہیں۔ وہ تو آپکی کوتاہیوں کا ذکر ہے۔ وہ لوگ تو ابھی چنے بھی نہیں گئے ہیں۔ جب چنے جائیں اور وہ اپنے کام کو انجام نہ دے سکیں تب کچھ کہیں تو بہتر ہے۔ سیوریج کی ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ گلی کوچوں کی صفائی کی ذمہ داری دی ہے۔ میونسپل کاؤنسلر کریں گے کیا۔ سیوریج ڈرینج کی صفائی کون کرے گا۔ کمال ہو گیا ہے۔ ایسی کچھ عجیب و غریب تقسیم کی ہے کہ بجلی کی ذمہ داری آپ نے لے لی۔ واٹر سیوریج بورڈ کی ذمہ داری آپ نے اپنے

آپ سپیا اوبھکیشن" شری شنکر دیال سنگھ:

براہ راست عوام سے۔ براہ راست جنتا سے تعلق ہوگا۔ یہ بل دلّی والوں کی خدمت کے قابل نہیں ہے۔ یہ بل لولا لنگڑا بل تک نہیں ہے۔ لنگڑا لولا گھسٹ تو لیتا ہے۔ لیکن اس میں تو گھسٹنے کی بھی گنجائش بھی نہیں ہے۔ میں جانتا نہیں۔ آپ لوک سبھا سے یہ بل پاس کرا کے لا چکے ہیں تو میرے یہاں کہنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے جو آپ لائیں۔ آپ نے گردن ہلا دی ہے۔ آپکے گردن ہلانے سے پہلے ہی میں جانتا تھا۔ اس لئے میرے یہاں بولنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میں ویرتھ بول رہا تھا۔ میری آواز تو ایسی ہے جیسے اکیلا کوئی صحرا میں گونج رہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں۔ دلّی والوں کے جمہوری حقوق چھیننے کا کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ۲۰ سالوں سے یہ کہانی برابر چل رہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا دقفہ ہماری گنہگاری کا بھی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ صدر صاحب کا۔

चौधरी हरी सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, यह राजधानी से संबंधित बिल है और इस बिल को पढ़ने से लगता है कि हमारे जो राजधानी के नागरिक हैं, उनके जीवन में बदलाव आएगा । जैसे कि अभी हमारे विरोधी दल के नेता आपकी बीच में नहीं रोका।

شری سکندر بخت: میں نے عرض کیا تھا جس وقت آپ گھنٹی بجائیں گے میں بیٹھ جاؤں گا تو صدر صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کارپوریشن لولی لنگڑی بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ بیساکھیاں لگا کر بھی نہیں چلا سکتے ہیں۔ چنے ہوئے لوگوں کا ایک کمال ضرور ہوتا ہے کہ آپ لاکھ گالیاں دیں دے دیجئے کہ تم چنے ہوئے لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم اس کارپوریشن میں اپنی مرضی کے لوگوں کو ملازم رکھ سکو۔ کیوں کہ تم کرپٹ ہو مگر یہ کارپوریشن کے ممبر جو ہوں گے ان تک لوگوں کی آواز تو پہنچ جاتی ہے۔ اپنی آواز نارتھ بلاک تک کیسے پہنچائے گا دلّی والا۔ کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جو آج چھوٹی چھوٹی خدمت کرنے والے ہیں۔ وہ چننے والے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے مؤدبانہ کہ آپ دلّی والوں کو کھلے دل سے جمہوری حقوق دیجئے۔ کھینچ تان کر مت دیجئے کہ جیسے پتنگ کو کبھی ڈھیل دے دیا۔ کبھی کھینچ لیا۔ بھرپور اختیارات دے دیجئے میں سمجھتا ہوں۔ جس قسم کا نکما کاروبار اب تک چلتا رہا ہے۔ اس میں امپروومنٹ تو ہوگی ہی کیوں کہ چنے ہوئے لوگوں کا

जिक्र कर रहे थे कि अब बिल्डिंगों के बाई-लाज बनाने का सारा का सारा काम सरकार को मिल जाएगा और जो चुने हुए लोग हैं उनके हाथ में कुछ करने-धरने को नहीं रहेगा । महोदय, आप देखते हैं कि बड़े-बड़े शहरों में मनमाने तौर पर जिसके दिल में जहां आता है चाहे वह सड़क हो या गली की नुक्कड़ हो, चाहे आम रास्ता हो वहां जबरदस्ती जमीन घेर लेता है । उसको वर्षों तक इस्तेमाल करने के बाद किसी न किसी तरह से उसका लीगल राइट भी हासिल कर लेता है । इस बिल में ऐसी चीजों का भी जिक्र किया गया है और उनका उपाय भी किया गया है । इस बिल के पास हो जाने के बाद जब यह बिल कानून बन जाएगा तो इस तरह से मनचाहे तौर पर बिल्डिंगें बनाना, आम लोगों के इस्तेमाल की जगहों को जबरदस्ती घेरना, इन सब पर पाबंदी लग जाएगी । दूसरा जो एम० सी० डी० के, स्थानीय निकायों के काम होते हैं, आप जानते हैं कि यह बड़े ढीले-ढाले ढंग से चलते हैं । उनको कुशलता, चतुराई और जल्दी से निपटाना, पूरा करना, वक्त के मुताबिक काम करना और करवाना या जो विभाग नागरिकों के जीवन से ताल्लुक रखने वाले हैं उनमें चुस्ती लाना और काम जल्दी निपटाना, इस बिल का मुख्य उद्देश्य है । इस बिल के मुताबिक सारे का सारा जो प्रशासन एम० सी० डी० का है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है । उसका डिवीजन कर दिया गया है । वार्ड कमेटी बना दी गई है और असलीयत में जो प्रशासन का काम है, वह वार्ड कमेटी तक पहुंच जाएगा, तो जो सेंटर के पास दौड़ कर जाना पड़ता था, दफ्तर में भीड़ लगा कर बैठे रहना पड़ता था, वह समाप्त हो गया है ।

तो यह बिल अपने में संपूर्ण बिल है और इससे दिल्ली के नागरिक की जो चुनाव संबंधी समस्याएं थीं, जो यहां पर ट्रांसपोर्ट की, स्कूल की समस्या थी, वाटर-लागिंग की समस्या का जैसे जिक्र कर रहे थे, इन सबके बनाने के लिए अफसरों की नियुक्ति और उनसे योग्यता के साथ काम लेने और पनिश करना—यह सारी चीजें इस बिल के अंदर आ गई हैं ।

आप जानते हैं कि अब तक जो कानून था, वह बहुत ही ढीला-ढाला और सुस्त कानून था । उसमें अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही हो—हम जानते हैं कि दिल्ली में मलेरिया और वाटर-लागिंग से और अनेक तरह की बहुत सारी जो कठिनाइयां, बीमारियां होती थीं, मुसीबतें होती थीं, उससे बहुत सारे नागरिक मर जाते थे । लेकिन उसकी दुरुस्ती के लिए कोई कानूनी शक्ल या हाउस में कोई मजबूती नहीं होती थी ।

इस बिल के साथ जो गैर-कानूनी चीज है, जो अधिकारी है या नागरिक हो, चाहे वह मनमानी ढंग से कोई चलाने वाले हों, या हमारी डिसपेंसरी हो या अस्पताल हो, इन सबका उपाय इस बिल के अंदर आ गया है ।

तो, मैं जैसा कह रहा था कि यह बिल बहुत अच्छा है और बड़े वक्त से लाया गया है । वैसे दिल्ली में अब असेम्बली भी बनने वाली है और उसके चुनाव की बहुत आशा है । बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे । यह निराशा का जो वातावरण बनाए हुए हैं—यह वह लोग हैं जो सोचते हैं कि जिनको न चुनाव लड़ना है और न जिनको कभी उम्मीदवार बनना है । लेकिन आज सारी दिल्ली में चुनाव का वातावरण बना हुआ है और सब लोग तैयारी कर रहे हैं और मुझे तो यह उम्मीद है, पालिटिक्स में रहने की वजह से मैं जानता हूं कि दिल्ली के चुनाव बहुत जल्दी होंगे और चुनाव होने के बाद, जो नया संविधान है, उसके मुताबिक प्रशासन करने का हक, जनता के जो चुने हुए लोग हैं, उनके हाथ में जाएगा । लेकिन यह बात जरूरी है कि कैपिटल चाहे न्यूयार्क का जिक्र हो, चाहे वाशिंगटन का या लंदन का हो, डायर्किकल सिस्टम नहीं चल सकता । यह हो सकता है कि कभी एक पार्टी की सरकार हो सकती है और कभी नहीं हो सकती है । तो रोज की खींचतान के लिए रोज कुछ कहेंगे कि उसका स्वागत हो, इसका नहीं हो, यह हमारी आइडियालोजी के मुताबिक है, यह हमारी पार्लियामेंटरी सिस्टम के मुताबिक यह काम करना मुनासिब है या नहीं, यह बहुत सारे डायर्की के जो दुष्परिणाम हैं, रूल जो होता है ना, उसे एवाइड करने के लिए । इस बिल में बहुत से सुधार लाये गये हैं और यह असेम्बली जो बनेगी, उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है । तो मेरे साथी और बुजुर्ग—मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, वे चले गये हैं, वह जो कह रहे थे कि जनता के हाथ में ताकत नहीं दी जा रही है, यह बहुत दूर-दराज से सोची हुई स्कीम जो है, उसका नतीजा है । स्वोई आफ रूल किसी भी स्थिति के लिए, किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता है । तो उसका भी उपाय इस बिल के अंदर आ गया है और असेंबली का भी आ गया है ।

जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह बिल अपने में बड़ा संपूर्ण है और यह नागरिकों के जीवन को चाहे वह हेल्थ से ताल्लुक रखने वाला है, चाहे वह एजूकेशन से ताल्लुक रखने वाला है, चाहे झुग्गी-झोंपड़ी का सवाल है, चुनाव का सवाल है और रोजाना की जिंदगी में जो रोज नई बस्तियां बनती हैं, उनका सवाल है, पानी का सवाल है, हमारी जो नई-नई योजना, जो

हमारी समस्याएं हैं, उसके लिए पूरा समर्थन और पूरी ताकत इसे सुचारु रूप से चलाने के लिए दी गई है।

मैं समझता हूं कि उपसभाध्यक्ष जी मेरी तरफ कोई इशारा कर रहे हैं। मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एम० सी० डी० में इत्तिफाक यह है कि हमारे बहुत सारे फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, कुछ और मजदूर हैं, भिश्ती हैं, दुनियाभर के कर्मचारी लोग वहां काम करते हैं। दुर्भाग्य है कि उनका एम० सी० डी० के अंदर कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है। मन के मुताबिक जब जी चाहें किसी का प्रोमोशन कर देते हैं, जिसको चाहा हटा दिया या ईनाम दे दिया। बीसियों साल से लोग पुख्ता ही नहीं हुए। जो इस तरह की कारगुजारियां एम० सी० डी० के मौजूदा शासन में हैं, इस पर हमारे मंत्रालय को नजर डालनी चाहिए और आये दिन एम० सी० डी० के लोग सफाई कर्मचारी, खास तौर पर हड़ताल करते रहते हैं, धरना देते रहते हैं और उनकी शिकायत होती है कि उनका एरियर और वृद्धि नहीं मिल पाती है। उनकी भरती का कोई नया सिस्टम नहीं बनाया जाता, जिसके मन में जैसा होगा, वह भरती कर लेता है, दूसरा कोई अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटर आया, तो उसने अपने तरीके से कर लिया। यह जो सिस्टम है, यह जो सफाई कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, वार्ड ब्वाय होते हैं, अस्पतालों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, इन सब को अंधाधुंध तरीके से जिसका कोई हिसाब नहीं है, किया जाता है जो बड़ी तकलीफदेह बात है। लोग मेरे पास आते हैं। मैं लिख-लिख कर थक जाता हूं। हमारी कोई सुनता नहीं है। वह कहते हैं कि हम तो ऑटोनोमस बॉडी हैं, यह सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इस बिल से प्रशासन में जो ढिलाई है, उसमें चुस्ती आएगी। लेकिन जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, उनके साथ एम० सी० डी० के अन्दर आज बड़ा अन्याय हो रहा है। उनकी अप्वाइंटमेंट का कोई सवाल नहीं है। रिटायरमेंट के बाद पैसा पूरा नहीं मिलता है। जो सफाई कर्मचारी मेनहोल्ज में डूब कर मर जाते हैं, उनको प्रोपर मुआवजा नहीं मिलता है। उनके मरने के बाद उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाती है। हर साल दर्जनों सफाई कर्मचारी मेनहोल्ज में डूब कर मर जाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनका कोई इन्श्योरेंस नहीं होता है, उनको रुपया नहीं दिया जाता है, जो एक लाख या दो लाख धनराशि की भरपाई है, वह भी नहीं की जाती है। नियमों के रहते हुए भी इस तरह की बदइंतजामी चल रही है। मैं आपका विशेष रूप से ध्यान खींचना चाहूंगा इस वक्त बहुत-से जनकल्याण के कार्यक्रम हमारे शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, दलितों के लिए स्कीम्स चल रही हैं। नेशनल कमीशन शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए बना है। सफाई कर्मचारियों के लिए लोक सभा में बिल पास हो चुका है और राज्य सभा में होने वाला है। लेकिन करोड़ों-लाखों की तादाद में जो नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों और एम० सी० डी० में सफाई कर्मचारी है, इनका जीवन बहुत दुखी है। इन लोगों को क्वार्टर नहीं मिल पाता है। वर्दी नहीं मिल पाती है। आखिर कौन करने वाला है, कब करेंगे, यह सब आपको देखना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी तरफ से कि वे इसके लिए एक सब-कमेटी मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट की बनाएं। यह कमेटी इस बात को देखे। जो सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्कूलों और अस्पतालों में सफाई का काम करते हैं चाहे वह किसी भी जाति के हों, उनकी प्रोन्नति के बारे में, अप्वाइंटमेंट के बारे में, मौत के बाद आश्रितों को सर्विस दिए जाने के बारे में, इन चीजों को देखने के लिए एक सब कमेटी बनाएं जिससे इन गरीब लोगों को जो कठिनाई है वह दूर हो सके। जैसे कि मैंने आरंभ में कहा कि यह बिल बहुत अच्छा है और जिन कठिनाइयों का मैंने निवेदन किया है वे शायद इस बिल से कुछ दूर हो सकेंगी और इन मौजूदा हालात में जिन उपायों का मैंने निवेदन किया है, उनकी ओर आप ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am greateful to you for calling me to speak on this important Bill. On a personal note, I may say that for a considerable portion of my life I have been associated with the civic affairs of Delhi. Therefore, in a way, not only as a citizen but also as a person who has been associated with the New Delhi Municipal Committee, I have some idea of how this city has been run from time to time. It is now more than four decades and almost at the turn of every decade we have got together to look at new arrangements in the Delhi Administration. There are some problems of Delhi which are of long standing. One of them is what type of administration should be given to Delhi. I recall that Shri Gulzari Lal Nanda, when he sat on your seat, Sir, at that time we discussed as to what the future set-up of Delhi should be. We were confronted with two or three basic issues. Of course, there was controversy whether Delhi should have the status of a State or not. I think by and large there has been a feeling that it is better not to have the status of a State for the obvious reason that it is the seat of power of the Central Government. Therefore, to have two States run parallel in

one city can create problems. I conceded that point. But I went one step further. That was whether we could create in Delhi itself some sort of an administration which could give satisfaction to the people. We have made various experiments. We have been making one experiment after another but without attending to two or three basic issues. One of course—it is a standing grievance of Delhi citizens—has been that there is no unification of the administration. Every new Act, every new law that we have brought has never attended to this problem. The end result is that only the names have changed—sometimes we; called it Metropolitan Council, sometimes we called it Assembly, sometimes we called it Corporation. We called it with one name or the other but the real issue did not attended to. One of the main issues, particularly in the sphere of civic life—I am attending to civic life first—has been that we have got a massive city now. It is one of the largest cities in the country, not only in the country but, perhaps, in the world. This needs a great deal of management, management not only in terms of administration, but in terms of public association with this vast expanding city. Every year, at every, turn of events, we find that the administration is going down. Today, unfortunately, we have come to a stage when we have acquired the distinction of this Capital of great India being the most polluted city in the country. We have been talking that pollution has been caused by traffic, by the increasing number of vehicles, etc. Yes, but what is the effort to contain it? I see nothing but advertisements issued from time to time. Besides this, we, in this House, hear statements from one Minister or the other or hear the traffic police saying, please dont' do this, please don't do that. There are cities in the world which are larger than ours, where traffic is far larger than ours and in those cities, pollution has been tackled. But the worst dimension of pollution is the type of garbage that you see here. It is very sad, you know, for those of us in this House, who have the privilege of sometimes travelling outside in various parts of the world, to see the lack of cleanliness here. Well, one can always find an excuse for not cleaning the city. One can always find] an excuse; well, the city is very large and! we are poor and, therefore, it has to be} a dirty city. Now, dirt squalor and litter are part of the city. We have to recon-cile with it. Then, of course, we can naturally say that there canont be any improvement. It could be said that this is one aspect, one dimension of the bad civic management. Nowhere in the world will you see such monumental garbages being piled on the roadside, where all the household garbage is first collected. Then, it stinks there for quite sometime and then it is removed, if at-all. For four decades—I may bring it to the notice of my worthy colleague, the Home Minister—seminar after seminar was held. I recall the seminars of 1960's. I recall the seminars of 1950's. We have the privilege of having Shri Jagmohan in this House who had, himself as Vice-Chairman of the DDA, called some seminars where we discussed that this could be upgraded. Nothing is done. Leave alone the whole city, even the New Delhi Municipal Committee, which is directly under the administration of the Centre, even there we have not tried to see that at least the environment around the Capital is improved, removal of garbage and litter is done somewhat more scientifically, somewhat more methodically. The net result is that as the time passes, the city becomes more and more dirty. The net result is pollution becomes the order of the day. The net result is, health hazards keep on increasing. The net result is, in every part of the city, you will find open drains. I will give one example—here I may sound somewhat personal—the area in which I live is South Delhi, which is thought to be one of the best administered areas in the city. A very huge *nulla* is flowing here. All types of diseases emanate from it. Three times I have personally gone to the Lt. Governor. Three Lt. Governors have changed in the meantime. I have gone to all these three Lt. Governors. Every time, we were told that this *nalla* would be covered because it was going to be somewhat of a commercial proposition. After covering the *nalla,* they would use the land so acquired for a purpose. But no action has been taken. This is one area. There are other areas which are worse than this. Today, you see newspapers reports, after the recent rains, about the type of lack of civic amenities. I saw that day that my colleague and friend, the Minister of State for Home Affairs, Mr. Sayeed could barely save himself from being drowned. I think he was about to be drowned in a street. If he got drowned, the local people would have seen to it that he did not come back alive. It is not because there is anything against him. It is because they are really fed up. A stage will come when people will do this and that has happened several times. A stage comes in the lives of the cities that the people just get fed up. When we started this city, it was a planned city and, thanks to the late Jawaharlal Nehru, we also decided, after partition that the city should grow according to a method and we thought that a methodical growth would be there. We had the First Master Plan and we had the Second Master Plan. We had the DDA then. What is the shape

of things? Master Plans are more flouted than followed. With regard to the Master Plans, every political party—I include this side of the House also— takes pride in saying that they would do this and they would do that at the time of elections and when they come to power, the first thing they do is to try to see how best to defeat the Master Plan. How do we save the city like this ? Here I would like to make a reference to Mr. Jagmohan and pay compliments. Unfortunately, he went into politics which he should not have done, because he was one of the best city administrators that I have known in the world. I am saying this since I know him, not only as a colleague and friend here, but also as the former Vice-Chairman of the DDA. When I was responsible for the Ministry of Works and Housing, he was the Vice-Chairman of the DDA and I have seen, given the will, how much good work can be done. But what, unfortunately is happening is that that will is lacking. Therefore, we go on making a plethora of laws and a plethora of rules and regulations which do not take us anywhere. Therefore, I want to draw your attention, Mr. Minister, to the stinking and sinking city that our Capital has come to be and I think that unless you possibly do something—do not give a proforma reply— and unless at your level and at the level of your Minister, Mr. Sayeed, who is otherwise well educated in the civic sense, you definitely pay some attention to this, things will become worse. This Capital city is the pride of our India and the pepole should definitely derive some sort of inspiration from this city. Can any citizen of India, who-comes to Delhi and goes back, say, "I have been to the Capital of India which is better than my city"? And, Sir, this is something which we should look into.

The difficulty at the moment is that the Municipal Corporation of Delhi is one dimension and there is the smaller dimension, the NDMC is totally administered by one person. There were years when we had at least nominated members when I had the privilege of being a nominated member of the NDMC for several years. At the time of the British, the practice was changed and they decided to bring in eminent citizens as nominated members of the NDMC. Now, we are a democratic society and therefore, we thought that we should have elected members. Whether elected or nominated there is the Administrator or President, whatever you may call him. But what is the result? Mr. Minister, you or your colleagues should go into the city and come "back and see whether the NDMC maintenance of roads, sanitation etc. is better than in the stinking and sinking part of the Municipal Corporation of Delhi. Why not bring in some citizens whom you rely on and who have your patronage? Your party may get some votes also. So, bring in *some* people whom you rely on. Kindly look into this question.

Now, come to the question of the Municipal Corporation. You see, from the very beginning, I was saying that we have been thinking in terms of having some sort of administration here. The world today has known only two types of city administration—one is the weak-Mayor cities and the other is the strong-Mayor cities. For forty years, we have had only a weak-Mayor city. We give all the powers to the Commissioners. But have they delivered the goods? . For the last two or three years particularly, can anyone justify the bad state of affairs on this basis that the party members, elected members do not allow the Commissioner to function? For the last three or four years there has been no election. There has been the Administration and no interference from the people's representatives. But have things improved then? Have the Commissioners delivered the goods? Have the nominated people, I mean, the bureaucrats, to whom you have handed over the city, done something better for the city? They have not done anything. Then how do you believe that under the new set-up that you are thinking of things would be much better than now? Mr. Jagmohan started a new experiment in making the city a strong-Mayor city. At the time of Mr. Gulzari Lal Nanda, we had also thought of the idea of trying to have a. Cabinet-type council to the Mayor. We thought of giving powers to the Mayor and giving him a Cabinet-type Council so that they could manage the city. But again you have gone back. And, particularly, we have gone back in a year and on a day when, I think, we are celebrating tomorrow the birthday of a very important citizen of India, Mr. Rajiv Gandhi. And you are taking pride in the type of Bills that we are passing and in a new system. I have before me the Constitution. (Seventy-fourth) Amendment Bill in which you are thinking of giving more powers to the civic bodies and, at the same time, you are passing a law which totally denies these powers to the elected members. What is the idea? Why do have this type of a farse played before us? A large number of Members will be elected. They will have no powers at all. The Mayor will be ceremonial, whether it is a lady or a man. And then you go on thinking that these very Commissioners and this very plethora of bureaucrats will make the city administered better. I have my grave doubts. And I have before me the experience of last four decades. And I have also the experience of having been

the Vice-President of the New Delhi Municipal Committee and also the Minister in charge of what you call the Ministry of Housing and Works. Therefore, may I suggest...(Time bell). Give me a few more minutes, Sir. Therefore, don't stick to the idea that since you have made up your mind to go along a certain path, you don't wish to improve the fate of the city.

Similarly, I would say about this thing, the DDA. For several years, we have been discussing that DDA has become totally unmanageable—housing, land acquisition, city planning, etc. Debate after debate, seminar after seminar, symposia after symposia have been held in the city to try to think that the DDA should be split into two or three parts. There has been no action. The result is that there is a strange type of cynical indifference on the part of the Union Government to the affairs of the city. And I want to go to another dimension of our city life. And I hope, it has come to your notice. And that is, all is not well in the city's empire. There is corruption. One can say, all right, corruption is a universal phenomenon, it is an international phenomenon, corruption is also there at the high levels in politics, highest people in the country are now accused of corruption, and so, why worry if somebody else is corrupt. In my 40 years of living in this citv, I do not know any other era when the Municipal Corporation was more corrupt than today, when it is more brazenly corrupt, when it is more openly corrupt. If you. Mr. Minister, spare about half an hour one day—don't tell that Mr. Chavan is going to visit such and such area—and go round the city and ask the people what they think of the corruption, they will tell you—and I can tell you—that nothing can be done in the city, whether you want a water connection or you want an electric connection or you want a sewer connection or you want to get your house plan approved or you want to get your completion certificate, nothing can work except by giving money, howsoever high and mighty you may be. Maybe, Mr. Minister, if you build a house, they may not ask you for money. But God is kind to you. YOU are not building a house. Don't do it. It is very dangerous to build a house in the city because you will be asked to pay money for everything. And how had it happened ? Primarily it is because—I would not say primarily—partly it is because the local people have no say in the matter. You have made the bureaucrats so powerful and they are all in league. And that is why I say that the things are not so good. You are taking away DESU and Water. That does not mean that you are going to change things. DESU is highly corrupt. And I do not know how you are going to change it. Same people will go on administering it. The only thing will be that even a few elected members of the Municipal Corporation will have no say in the matter. Therefore, again, you are taking it away thinking that the bureaucratic system is the best system. It is a very ironical situation. We the elected Members of Parliament, we the elected Members of the Assembly, somehow or the other, continue to believe that the worst disease for the country is the elected member. Therefore, we try to think that the elected members cannot do anything, the bureaucrats can deliver the goods. Even then, we go on seeing things before our eyes. And, Sir, you kindly give me a couple of minutes to talk about the Bill itself.

Sir, in the Bill, I see something strange. There are two points, particularly. One is, of course, you are talking in terms of it that the total shall not exceed 184. Why not? What is sacrosanct about it? If you cannot manage the population, if the population is going to increase, whose fault is it? We had frozen the membership of Lok Sabha for a different reason altogether. I hope you recall that we decided to freeze it—one, because the hall could not be expanded indefinitely and secondly, it was antifamily planning. But in the civic sphere, you cannot have that. As a matter of fact, the better thing for Delhi would have been if you had split Delhi into 4-5-6 municipalities and kept two or three subjects under the Centre, either under the Assembly you are creating or under the centralised mayor. But anyhow you have not done it. Therefore now you are going *to* make these constituencies so large and so unmanageable. The essence of good administration of civic life is that every elected member should be accessible to every electorate, to every person. He should be a next door man to whom one can go and tell where the shoe is pinching. But you are making the constituencies so large that you do not know the next door man, he may be remote because he is elected on the basis of a very large constituency. I think this needs attention once again.

You have taken the provisional population figures. Again it is the same thing when you say that it will be the basis. But is it not our experience that Delhi is expanding very fast? Is it not our experience that the projected population by the end of the century is going to be much larger that it is today? Is it not

our experience that the way we are expanding, the municipal corporation is bound to be more inefficient and more ineffective than it is today?

You have also said in one amendment that you will reserve seats for women. I welcome the idea. But you say that the Government will decide, which seats and where. Why should the Government decide? Why can't the municipal committee itself decide? Why can't the elected members there decide? Why can't this power be given to them? At every stage we are going to bring in the Government. This is one of the difficulties of Delhi life because you do not let the autonomous corporation, the autonomous civic life come up in the city. Lesser the autonomy, more is the interference of the Government and the end result is that what we are talking of all the time of what you call the new amendments or the new dream of village life, becomes a farce. Therefore, at least in Delhli, we must do something about it.

We are also talking of dissolution. I think one of the major failure of civic life in Delhi and elsewhere in the country has been this power to dissolve the elected corporation. I would rather feel that something else is thought about it because of the way it has been practised. *In 40 years, how many times* and for what reason have the Delhi Corporation or the municipal committees been dissolved? I have also had the privilege of sitting on that side of the House and I can say that mostly it has been dissolved for political reasons, not for civic reasons. In this context, the interesting part of it is that while the municipal committee or the corporation can be dissolved at your *sweet* will, it says that the Commissioner shall not be removed from the office except in the manner or the ground the Election Commissioner is removed. They are like the High Court Judges. Now you are creating one more Mr. Seshan. We had one enough and you are creating one more man on the pedestal. Who will select the Election Commissioner? How will he be selected ? Will it be the discretionary power of the Government only or do you want to create a panel here? At least make an experiment. Involve the local people. Involve the corporation mayor in it. Involve the locally elected people so that they can decide what type of Commissioner you should have.

Finally, the administrator's powers are diabolical once again. Again this is a plethora, *Corporation does not function* because the Commissioner is not there. Elected members cannot function. Central Government comes in on several occasions. The Administrator comes in on more than one occasion. Therefore, the total picture that is emerging before us is that we are going to have one more organisation that is bound to fail to deliver the goods and that is bound to frustrate us *still* further. As a citizen, I strongly protest against this.

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे चिट्ठी लिखने की जरुरत पड़ी और मैं जब लेने के लिए स्टोर गया ..

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : यह व्यवस्था का प्रश्न कहां है ।

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान : हां, है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ब्रम्हदेव जी आप बैठिये ।

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान : नहीं, नहीं । लोकसभा में ..... (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : ये प्रिविलेज का प्रश्न रख रहे है कि एक जगह स्टैम्प्ड पोस्ट कार्ड मिलता है लोक सभा में और यहां मिलता है अन-स्टैम्प्ड ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सुन लीजिए ब्रम्हदेव जी ..

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान : आप सुन लीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : एक मिनट आप बैठ जाइये ।

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान : यहां अंग्रेजी में मिलता है वहां हिंदी में मिलता है । मैंने कहा कि मुझे हिंदी में चाहिए, कहा कि नहीं मिलेगा राज्य सभा में ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): अच्छा ठीक है । सुन लीजिए । यह बात मैं सेक्रेटेरियेट को कह देता हूं । ये सारी बातें जब-तब नहीं उठानी चाहिए । आप एम०पी० है । आप लिख देंगे और नोटिस आफिस में दे देंगे तब भी उसकी सुनवाई हो जाएगी । आप इसको नोटिस आफिस में दे दीजिए उस पर सुनवाई हो जाएगी ।

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान : नहीं । उन्होंने कहा कि हिंदी में छपता ही नहीं है, अंग्रेजी में ही छपता है । इसीलिए मैं कहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ठीक है । उसके लिए भी आप कह दीजिए । श्री विश्वजीत पृथ्वीजित सिंह । उपस्थिति नहीं है । श्री सत्य प्रकाश मालवीय ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (संशोधन) विधेयक है, इसके आने के पहले मैं यह समझता था कि जो पुराना दिल्ली नगर निगम विधेयक है या अधिनियम है उसमें काफी सुधार किया जाएगा और सही मायने में दिल्ली के नागरिकों को स्वयं शासन करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह दिल्ली के नागरिकों के साथ एक बहुत ही क्रूर मजाक है और इसमें जो दिल्ली के विधिवत् निर्वाचित उनके मेम्बर्स होंगे या मेयर होंगे उनको कुछ भी अधिकार नहीं दिये गये है। आजादी के पहले इस देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो ये जो स्वायत्त सेवी संस्थाएं या स्थानीय निकाय थे यहीं पर उस समय हमारे देश के बहुत बड़े-बड़े सेनानी म्युनिसिपल कारपोरेशंस के मेम्बर्स होते थे और ये एक प्रकार से परीक्षण का केन्द्र रहते थे। लेकिन यह जो आज विधेयक लाया गया है इसका मैं पूरे तरीके से विरोध करता हूं और उसके लिए मेरे पास बहुत से कारण भी है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो इसके प्रावधान है केवल मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। पहली बात इसमें दी हुई है —

> "The Corporation shall be composed of the councillors;
>
> the following persons shall be represented in the Corporation. namely :—
>
> ten persons, who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or experience in municipal administration to be nominated by the Administrator."

एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कहा गया है कि जो दिल्ली के उप राज्यपाल या लेफ्टिनंट गवर्नर होंगे वे ही एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसा कि सभी को विदित है कि जो दिल्ली के उप राज्यपाल हैं वे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कारपोरेशन के दस लोगों को नामांकित करने का अधिकार देना कहां तक उचित है। इसका मैं कोई भी औचित्य नहीं समझता हूं। आप नामांकन का अधिकार दीजिए लेकिन मेरी समझ से यह अधिकार जो कारपोरेशन के चुने हुए सदस्य है उन्हीं को आपको देना चाहिए। दूसरा पहले इसमें एल्डरमैन का प्रावधान रहा करता था, उस एल्डरमैन के प्रावधान को जहां तक मैं समझ सकता हूं आप हटा रहे हैं इसलिए मैं इसमें तनिक भी औचित्य नहीं मानता हूं कि जो व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो उस व्यक्ति को दिल्ली के दस सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार दिया जाए।

दूसरा जो कारपोरेशन है इसको भंग करने का भी प्रावधान किया गया है। अभी गुजराल जी के भाषण को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने स्वयं इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है। जब से दिल्ली कारपोरेशन एक्ट बना है तब से लेकर आज तक यदि गिना जाए वर्षों को तो ज्यादा वर्षों तक दिल्ली का जो कारपोरेशन है वह लम्बित रहा है, कम अवधि के वर्षों तक दिल्ली में निर्वाचित कारपोरेशन या निर्वाचित सदस्य रहे है और आपने इसमें कोई कारण नहीं दिखाया है कि कारपोरेशन यदि भंग किया जाएगा तो क्यों भंग किया जाएगा, क्या उसके कारण रहेंगे ? इसलिए इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। कोई बहुत ही विषम परिस्थितियां हों, कोई बहुत ही आपत्काल परिस्थितियां हों तो मैं इस बात को मानता हूं कि यह अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह अधिकार इसके हिसाब से आपने अपने हाथ में लिया है। दिल्ली की विधान सभा बनने जा रही है। वहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। वहां पर एक लोकप्रिय सरकार होंगी। तो पहली बात तो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में आपको कार्पोरेशन को निलंबित करने का अधिकार रखना चाहिए और वह भी जो निर्वाचित लोग हों, उनके जो प्रतिनिधि हों, उनके हाथ में अधिकार देना चाहिए।

तीसरे, इसमें आपने चुनाव आयोग की चर्चा की है। दिल्ली की जो नैशनल कैपिटल, टैरिटरी आफ् दिल्ली होगी उसके लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाएगी और उस चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा ? वही एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक यानी कि दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर। इस प्रावधान में भी मुझे बहुत दुख और बहुत कड़ी आपत्ति है कि दिल्ली के लै० गवर्नर के चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का आप अधिकार देंगे। चुनाव आपको कराना है, चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव भय-रहित वातावरण में हो, इसलिए चुनाव आयोग होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की कौन नियुक्ति करेगा, वह अधिकार आप लै० गवर्नर को मत दीजिए। उनको नियुक्त करने के लिए जब इस देश में चर्चा चल रही है कि वर्तमान में जो चुनाव आयोग है इनको नियुक्ति करने की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। केवल जो कार्यकारी हैं, उनके हाथ में अधिकार नहीं रहना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके संबंध में भी आप सोचें और पुनर्विचार करें। लेकिन दिल्ली के चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार यहां के लैफ्टिनैन्ट गवर्नर को आप दें, इसको मैं किसी भी तरीके से उचित नहीं मानता हूं।

दूसरे, इसमें कोई व्यक्ति, यदि उस के खिलाफ शिकायत आती है, उस चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ तो आप ने इस बात की व्यवस्था जरूर की है कि चुनाव आयोग के पास लै० गवर्नर भेजेंगे और लै० गवर्नर और चुनाव आयोग जो कुछ भी फैसला करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे । मेरी समझ से इसमें भी परिवर्तन और संशोधन करने की आवश्यकता है ।

मैं एक और बात की भी सफाई चाहूंगा कि जहां पर आपने यह कार्पोरेशन को भंग करने की व्यवस्था रखी है तो मैं यह समझ पाया हूं कि पहले तो उसको शायद आपने बदल दिया है जिस वक्त इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग और यह कार्पोरेशन जो होगा ..... (व्यवधान)

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह 4.00 बज गए हैं और चार बजे लिस्ट आफ बिजनेस में ड्रग पालिसी को लिए जाने के बारे में है, तो इसको कल किया जाए या आज ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि यह बिल पहले पूरा किया जाए, उसके बाद उसे लिया जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : इसे पहले हो जाने दीजिए और अब यह तो बहुत कुछ हो गया है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO) : Just a minute, Mr. Vice-Chairman. How long will it take ? I am having the same thing .....

SHRI S. B. CHAVAN : Half an hour more.

SHRI EDUARDO FALEIRO : So, if you give me time at five O'clock, I will come here at five O'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : Within half an hour you may come.

SHRI EDUARDO FALEIRO : My Bill is there in the Lok Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : So. please go.

SHRI EDUARDO FALEIRO : So, at what time should I come ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) ; Please come after half an hour.

मालवीय जी, अब आप इसे तुरन्त समाप्त कर दीजिए । ..... (व्यवधान)

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Let him introduce it and go.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : बीच में नहीं । ..... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : नहीं, यह तो प्रस्ताव हो चुका है ।

He has already moved it last evening. You were not present, Mr. Sahu.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन के कार्यकाल को समाप्त करने का अधिकार जिस प्रकार से इस विधेयक में दिया गया है यह अलोकतांत्रिक है और जनतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है । इसलिए इस प्रावधान को इस विधेयक से हटा देना चाहिए । जैसा कि मैंने शुरू में कहा है जो इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, सदस्य होंगे या जो मेयर हैं, उनको आपने कोई भी अधिकार नहीं दिया है । मेयर केवल कार्पोरेशन की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता करेगा और इसके अलावा इस सारे अधिनियम को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि उनको तनिक भी अधिकार नहीं है और जितने भी अधिकार हैं वह आपके नौकरशाही के जो लोग हैं, जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको आप दे रहे हैं । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को आप वापस लीजिए । और उसको वापस लेने के बाद सही मायने में जो एक स्थानीय निकाय वाला विधेयक हो, जिसमें कि लोकल बोडी के सदस्यों को अधिकार हो, मेयर का अधिकार हो, अगर दिल्ली मेयर का प्रोवीजन है उनका अधिकार हो, इस तरह का एक नया विधेयक आप लाइए । यह आप इसी सत्र में इसी सदन में कर सकते हैं । इसमें कोई विलंब करने की जरूरत नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का अपनी पूरी शक्ति के साथ विरोध करता हूँ ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर के प्रशासनिक ढांचे का अपना इतिहास है । जब मैं इस पर नजर डालती हूँ तो मुझे यह लगता है कि दिल्ली नगर का इतिहास एक के बाद एक मनमाने ढंग से किए गए प्रयोगों का इतिहास है, जनतंत्र बनाम नौकरशाही की रस्साकशी का इतिहास है और जनतंत्र बनाम नौकरशाही की हर रस्साकशी के बाद मैं जनतंत्र को लहूलुहान होकर कोने में पड़ा सिसकता महसूस करती हूँ ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम के प्रशासनिक ढांचे पर जब हम बात कर रहे है तो सबसे पहले इस बात की ओर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि दिल्ली प्रशासन के साथ अब तक अभिनव प्रयोग किए जाते रहे हैं । अगर हम 1947 से देखें तो सन् 1947 में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ दिल्ली पर भारत सरकार का कब्जा था और आजादी के संघर्ष के दौरान जो जनतंत्र का मूल्य हमने हासिल किया उस मूल्य के चलते चारों ओर स्वशासन और जनतंत्र की घोषणाएं होने लगीं और उसी पृष्ठभूमि में यह आवाज भी उठी कि आखिर दिल्ली के लोगों ने कौनसा अपराध किया है जो दिल्ली के लोगों को जनतंत्र का अधिकार नहीं मिलेगा । इसी परिस्थिति में डॉ० पट्टाभि सीतारमैया के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ । सन् 1952 में दिल्ली को एक विधानसभा मिली और एक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर भी मिला । यह व्यवस्था सिर्फ चार साल तक ही चल पाई थी कि सन् 1956 में फिर उसको बंद कर दिया गया । राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल बनाई गई । उसके साथ ही जब पट्टाभि सीतारमैया की सिफारिशों पर बात हो रही थी उसी समय हमारी संविधान निर्मात्री सभा के पास यह चर्चा उठने लगी थी कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी पर संघीय सरकार का कब्जा रहना चाहिए या उसका नियंत्रण रहना चाहिए । उसी के चलते दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को लेकर लगातार अभिनव प्रयोग किए जाते रहे । इन प्रयोगों का सिलसिला जो चला तो कभी रुका नहीं । सन 1966 में दिल्ली प्रशासन द्वारा कानून पास करके प्रशासनिक ढांचे में एक और परिवर्तन किया गया । मैट्रोपोलिटिन कौंसिल बनाई गई । उसके बाद फिर 1971 में परिवर्तन किया गया, फिर 1977 में परिवर्तन किया गया । फिर 1987 में बालकृष्णन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तथा संविधान के 73 वें संशोधन के आधार पर आज हमारे गृहमंत्री महोदय यह संशोधन बिल लेकर आए हैं ।

महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक दिल्ली प्रशासन के साथ जो अभिनव प्रयोग किए जाते रहे है नौकरशाही और जनतंत्र के बीच तालमेल बैठाने के लिए और गृह मंत्री महोदय आज जो यह संशोधन विधेयक लेकर आए है उस संशोधन विधेयक की जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि यह विधेयक या संशोधन विधेयक एक तरफ विकेन्द्रीकरण का गौरव और दूसरी तरफ केन्द्रीकरण का सुख, विकेन्द्रीकरण का गौरव और केन्द्रीकरण का सुख, दोनों को समान रूप से भोगने की हमारी केन्द्रीय सरकार की जो मशक्कत रही, जो कसरत रही, यह उसी का एक अभिनव नमूना है, जो "आधा सीतर आधा बटेर" के रूप में यह दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल हमारे सामने आया है । मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल जो लाया गया है, यह वास्तव में नौकरशाही के इशारे पर लाया गया है और वास्तव में जनतंत्र की हमारी जो एक आकांक्षा थी कि दिल्ली की जनता की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए उसे जनतांत्रिक अधिकार दिए जाए वह आशा कहां तक इस विधेयक के जरिए प्रतिफलित होगी, इसके बारे में मुझे संदेह है । शुरू से ही हमारी दिल्ली की सरकार पर नौकरशाही का दबदबा रहा है और नौकरशाहों की हमेशा यह मंशा रही है कि राष्ट्रीय राजधानी पर तथा दिल्ली की सरकार पर इस तरह नौकरशाही का कब्जा बना रहे क्योंकि वही ढांचा उन्हें पसंद आता है और यही प्रतिछवि हमें आपके इस विधेयक में भी नजर आई है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो मैं इस विधेयक के संबंध में कहना चाहूंगी कि इसका कुछ सकारात्मक पक्ष निश्चित रूप में है । हमारे गृह मंत्री महोदय ने 73 वें संविधान संशोधन की रोशनी में पार्षदों में 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे है, इसका तो मैं उनका स्वागत करती हूँ । लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह आधे-अधूरेपन का एक स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है । एक तरफ तो मंत्री महोदय महिलाओं को 30 प्रतिशत स्थान देते हैं और नगर निगम के पांच वर्षों के काल में पहला वर्ष महिला के लिए सुरक्षित करते है मेयर के रूप में, लेकिन काल क्या है ? सिर्फ एक वर्ष । क्या महिलाएं आभूषण की चीज है कि उन्हें अलंकृत कर दिया जाए । एक वर्ष में महिलाएं क्या दे पाएंगी कारपोरेशन को ? हमारे यहाँ का तो इतिहास रहा है कि एक-एक नगर निगम मेयर के पास में जाने जाते रहे है । अब अगर हमारे गृह मंत्री महोदय यह प्रावधान लेकर आए है तो मैं समझती हूँ कि इस तरह एक वर्ष के लिए महिला, एक वर्ष के लिए ए० सी० एस० टी०, इससे मेयर का तो कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा और कारपोरेशन पर नौकरशाही का ही कब्जा रहेगा । इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे गृह मंत्री महोदय इस पक्ष पर सोचे और आप जो भी व्यवस्था करें कम से कम पूरे काल के लिए करें । महिलाओं के लिए भी करे तो पूरे काल के लिए करें, इस तरह की व्यवस्था मैं चाहती हूँ । इसके साथ ही साथ जो इसका सबसे नकारात्मक पहलू है, वह यह है कि हमारे गृह मंत्री महोदय ने इस विधेयक में यह प्रावधान रखा

है ...(समय की घंटी)... एक नगर पालिका का या नगर निगम का जो मूलभूत अधिकार होता है—पानी की आपूर्ति, मैला उठाना, हाउसिंग का निर्माण, ये तमाम चीजें इस बिल में कहीं परिभाषित नहीं की गई और इसके लिए कहा गया है कि इसके लिए डिफरेंट एजेंसियां होंगी, अलग एजेंसियां होंगी, लेकिन ये एजेंसियां क्या होंगी, इनका स्वरूप क्या होगा, इसका कहीं कोई उल्लेख हमें मिलता नहीं है । जाहिर है कि आज हमारी केन्द्रीय सरकार जिन नीतियों की ओर चल रही है, निजीकरण की जिन नीतियों की ओर, उन नीतियों का प्रतिफलन इस पर भी होगा और आज हम ऐसे सिद्धान्तकारों को जरूर पाते है जो लगातार नई-नई घोषणाएं करते रहे है कि अब चुने हुए प्रतिनिधियों की, मनोनीत सदस्यों की, निर्देलीय सदस्यों की जरूरत नहीं है, आज जरूरत इस बात की है कि विशेषज्ञों के हाथ में सब चीजें दे दी जाएं । विशेषज्ञों के हाथ में अगर सब चीजें दे दी जाएं तो कारपोरेशन का क्या मतलब रहेगा ? नगर निगम का मतलब यह रहेगा कि वह खाली टेंडर बुलाएगा और टेंडर पर निर्णय लेगा, निविदाएं जारी करेगा । यदि यह अधिकार आप नगर निगम को देना चाहते है तो यह जनतंत्र के नाम पर केवल एक धोखा है और कुछ नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जो हालत है, करोड़ों-अरबों रुपए खर्च किए जाते है लेकिन आज नागरिक सुविधाओं के नाम पर दिल्ली शून्य है । चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे है—पानी नहीं है, बिजली नहीं है, झुग्गी-झोंपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है । उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से दिल्ली के नगर प्रशासन के बारे में सी० ए० जी० की रिपोर्टों को मैं देख रही हूं । आप आश्चर्य करेंगे कि सी० ए० जी० की हर रिपोर्ट में ऐसी 30 से 32 घटनाएं गिनाई गई है जिनमें भ्रष्टाचार के मामले हैं, गलत निर्णयों के कारण करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है । आज हम देख रहे है कि दिल्ली में किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं पर, बालिकाओं पर, लगातार उनकी इज्जत लूटी जा रही है, अस्मत लूटी जा रही है । लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कर रही है ? दिल्ली पुलिस मामलों को सलटाती नहीं है, लगातार मामलों को बिना सलटाए रखा जा रहा है ।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह सब बात जो आप कह रही है, वह कारपोरेशन के अधिकार में नहीं आता है ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं कारपोरेशन के अधिकार की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा कितना सड़-गल गया है ।

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : नागरिक जीवन बर्बाद हो रहा है ।

†شری محمد امین : ناگریک جیون برباد ہو رہا ہے۔

श्रीमती सरला माहेश्वरी : नागरिक जीवन के नाम पर आपने क्या किया ? दिल्ली में करोड़ों-अरबों रुपए खर्च कर दिए ।...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : अब आप एक-दो मिनट में कन्क्लूड कर दीजिए ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आपने जो 30 प्रतिशत स्थान दिए, उसके लिए तो मैंने मंत्री जी का स्वागत किया, लेकिन एक वर्ष के लिए जो मेयर का पद दिया, उसके लिए मैंने विरोध किया । ..(व्यवधान).. महिलाओं के लिए आप कोई दान नहीं दे रहे है और न हमें कोई दान चाहिए । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहती थी कि अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि यह बड़े शहरों की क्या समस्याएं होती हैं । अमेरिका में शिकागो शहर की समस्या मैं पढ़ रही थी कि वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई जिसे मशीन फेज और पोस्ट मशीन फेज कहा गया । मशीन फेज के अन्तर्गत देखा गया कि उन्होंने इंटीग्रेटिड एजेंसी बनाई और एक समन्वय समिति के रूप में तमाम जो एजेंसीज थी उनके बीच में समन्वय करके काम चलाया । लेकिन जब पोस्ट मशीन फेज शुरू हुआ तो उसके चलते तमाम धांधलियां शुरू हो गई और रोगर्स ने जो अपनी पुस्तक लिखी — 'Problems of the Management of Big Cities".

उसमें उन्होंने यह बताया कि यह पोस्ट मशीन एरा जब शुरू हुआ तो जो मशीन एरा में समस्याएं थी और जो सुविधाएं थी उन सुविधाओं को तो, उन विकल्प को तो रखा ही नहीं, उस विकल्प के बिना रखे हुए ही उसको खत्म कर दिया गया और फिर जो उस पोस्ट मशीन काल में जो आए उसमें यह देखा गया कि उस काल में लगातार नौकरशाही का दबदबा जारी होता था और आज हम दिल्ली में देख रहे हैं कि इसी तरह एक नहीं एकाधिक एजेंसियां हैं, मल्टीपल एजेंसियां हैं । जनता शिकायतें लेकर जाती हैं, परन्तु उसे कहा जाता है कि हमारे अधिकारों में नहीं है, कोई बोलता हैं कि हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, जनता की कहीं सुनवाई नहीं है । स्लम

†[ ] Transcription in Arabic script.

एरिया की जो हालत है, डी० डी० ए० में जिस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है उसका तो एक किस्सा मैं खुद जानती हूँ जो मैंने मंत्री जी को दिया भी है । (घंटी)

उपसभाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक-दो मिनट और दे दें । तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है । परसों मैंने यह मामला उठाया कि किस तरह स्लम एरिया कानून के अनुसार यहां रहने वाले लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था के बिना हटा नहीं सकते । इसी तरह नाइजीरिया एम्बेसी का मामला है । तो दिल्ली में नागरिकों को सुविधाओं के नाम पर आज वास्तव में कुछ हासिल नहीं हो रहा है । रुपए खर्च किए जा रहे हैं, नौकरशाहों के हाथों खर्च किए जा रहे हैं । मैंने देखा कि सी० ए० जी० की रिपोर्ट में 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए 34 लाख रुपये आबंटित किए गए थे । वह 34 लाख रुपये डिप्टी कमिश्नर के आफिस में ही गबन कर दिया गया । उनका कहीं पता नहीं चला । मंत्री जी देखेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे पर अभी है ।

तो आप जब यह विधेयक लेकर आए हैं तो इस विधेयक से दिल्ली की जनता तो यह आशा करती थी कि इससे वास्तव में जनतंत्र को एक मजबूत पुख्ता स्वरूप मिलेगा, जनतांत्रिक पुख्ता ढांचा आप तैयार करेंगे । लेकिन वास्तव में उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस विधेयक को देखती हूँ और आप तो घंटी पर घंटी बजा रहे हैं । मंत्री जी ने . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : जो समय आपका निर्धारित था सरला जी, देखिए, मजबूर है इस बिल को तुरन्त पास करवाना । बस, आप समाप्त कर दीजिए ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उपसभाध्यक्ष जी । कितना मोटा संशोधन विधेयक मंत्री जी लाए हैं और इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर कुल डेढ़ घंटे का समय है । फिर भी मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म करना चाहूँगी कि वास्तव में एक बार सिर्फ इस विधेयक के जरिए नौकरशाही और जनतंत्र के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी, अभी भी मुझे पूरा संदेह है कि जनतंत्र शायद विजय हो पाएगा या नहीं ? लेकिन फिर भी आशा की किरण मुझे सिर्फ इतनी सी नजर आती है कि कम से कम एक प्रक्रिया तो शुरू होगी, एक जनतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होगी और जब जनतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होगी तो शायद जनप्रतिनिधि इस जनतांत्रिक प्रक्रिया के शुरू होने से इस विधेयक में जो नकारात्मक पक्ष हैं, वह उन नकारात्मक पक्षों को निरस्त करके सकारात्मक पक्षों को ला सकें । जब जनतंत्र का रक्त प्रवाहित होगा तो शायद मैला अपने आप निकल जाए । इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ ।

SHRI VISHVAJIT P. SINGH (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, I beg to make a request to you. As per the directive of this House, I have gone to the two Committees to which I am elected Member, by virtue of this House itself, the two Committees being the Joint Committee on Copyrights and the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. I have just come from there, after making my submissions. I have made my submissions in brief there and I have rushed back to the House. I request, Mr. Vice-Chairman, that I may be permitted to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : I have already called your name in your absence. So, at the end, if the Minister permits, I can give you some time.

SHRI VISHVAJIT P. SINGH: My party's time should not be taken away only because I was not here. We will submit another name from the party.

SHRI S. B. CHAVAN : You can speak after Mr. Jagmohan speaks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) : Shri Jagmohan.

[The Vice-Chairman (Shri Md. Salim) in the chair]

SHRI JAGMOHAN (Nominated) : Sir, I am a bit disappointed by this Bill and also by the other legislative measures that are being taken with regard to the national territory because all these measures ignore one basic point—what is our vision of the city ? What sort of a city do we want to develop ? We don't seem to be very clear about it at all. Are we matching our resources or are we considering the gap that exists between our requirements and our resources ? We do not seem to do so. Nor do we seem to go in a planned and purposive way. It is usually said, "show me your cities and I will • tell you about the cultural aims of the nation." I think seeing the city today, the culture of confusion, contradiction and callousness is all that is visible in our city today. You see, this is the city where 77 per cent of people live in slums and substandard houses; where there are 1,000 jhuggi-jhompris and there are farm-houses which have just bottled up the city for further extension. I need hardly say anything about water, electricity and sewerage. Sometimes, the blue buses kill and sometimes the *red* buses kill

There is lawlessness and disorderliness in the city. Whether you have the bureaucratic structure or the so-called democratic structure or a combination of the two, the basic issue is, unless there are committed and courageous people to create a new city, we will not be able to solve the problem. Unfortunately we are following a very imitative type of a model, a model which was there in the 19th century — Lord Rippon's model or the Western model — whereas our problems are entirely different. We have got a massive influx of poor people in our cities which is not found anywhere. We have no means to create resources. Our resources are very limited. There was a time when we created a new vision for the city and that vision was to create resources from within the city to heal the wounds which we had inflicted on the city. You know there, are seven cities of Delhi — Lalkot, Jahan Panah, Srri, Purana Quila, Ferozabad and so on—and their ruins were there. Then the seventh city was the Shahjahanabad and the eighth city was the Lutyen's belt. We wanted to build the ninth city which would be an amalgam of all these and Which will reflect our news aspirations. But that vision was blocked. Now, I can tell you a very simple thing. It was this vision which created resources from within the city by making use of the infrastructure and investment in the land. The urban land was made a great resource for the development of the city. All the green areas which you see in the city today, were created out of the land assets. It was because of the rising value of the land in the city. The rising value of the land occurred because public authorities were making investments and the advantage of the rising value was taken by us. My friend said, "our infliction on the city". Our friends aiso sometimes say that Mr. Jagmohan is ,anti-one community. I want to inform them that it was I who cleared all the slums and squalor around those historical places to create green areas and to maintain the historical and architectural legacy, whether you go to Purana Quila, whether you go to Hauz Khas, whether you go to Matka Peer, whether you go to Bazar-a-Medil, whether you go to Idgah Jama Masjid *or* whether you go to Qasabpura. What was there ? I removed these people, planted trees around the city and kept the architectural and historical legacy. This was the city.. . *(Interruptions).*

SHRI VISHVAJIT P. SINGH: He is admitting that he removed those people. *(Interruptions)*

SHRI JAGMOHAN : What 1 am saying is different. He is not following that. What] am saying is that this was the historical and architectural legacy of the Sultane period or the Moghul period which was maintained. I created the 'community green'. This was the vision by creating resources from within the city. This has nothing to do with X, Y or *Z.* My point is, a new innovative device was employed and was successfully employed. There was a provision for housing the poor. For example, the land was acquired in large scale and was distributed in accordance with the needs of the city and people were resettled where they were needed and it was not that the people occupied historical places or that land which was required for hospitals, schools and colleges was squatted up by them or the lands which are required for roads and bridges should be squatted upon. That vision is now gone. My suggestion is that this Bill does not provide an alternative vision. Unless you give a new creative impulse to the society, unless you have a new creative institutional framework, a dynamic, positive and committed' institutional framework, you will not be able to solve any of your problems, whether you employ 'X' patron or 'Y' patron or 'Z' patron. This is the unfortunate thing today. Everything is over-criticised. Even the construction of a small road is criticised. Every bureaucrat is prevented from doing what he wants to do. You will find that there are a lot illegal or unauthorised constructions and the irregular regularisation of those unauthorised constructions is the civic service that is being done today. I want to remind you of this basic issue. I want to remind you of what Gandhiji said about our Municipal Councillors what is actually being done. Gandhiji said, "I would advise the Municipal Councillor not *to* seek honours or indulge in mutual rivalries but to have a real spirit of service and convert himself into an unpaid sweeper and road-maker and, above all, *to* take pride in doing so." Where is the civic pride today ? There is no pride. There are no committed people. The city is in the hands of ravishers and rapers. You go anywhere in the squatted city. In the walled city of Delhi there are now half-a-million people living jam-packed in half-a-square mile area. It has the highest density *in the world* and you have also got the lowest density in the world at Prithviraj Road and Aurangazeb Road. This is the city which we want to integrate, where we want to build a road from Jama Masjid *to* Parliament Street so that the city would really reflect our new aspirations and build a green velvet from Jama Masjid right up to Rajghat. So, this was the basic issue which I was ... *(Interruptions)* ...This was the vision .,. *(Interruptions)* ...

SHRI SHAMIM HASHMI (Bihar): I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : What is your point of order ?

†श्री शमीम हाशमी : वाईस चेयरमैन साहब, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

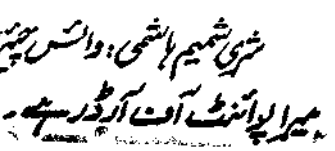

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : बताइए क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ।

†श्री शमीम हाशमी : अच्छे अच्छों के ये अच्छे है, हर बात ही इनकी अच्छी है, दुनिया को बुरा ये कहते है, दुनिया की बुराई इनमें है । . . . (व्यवधान)

तुम्ही कहो कि यह अंदाजे गुफ्तगू क्या है ?

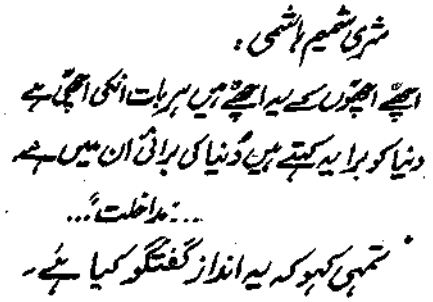

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Anyway, don't create disorder. You please sit down. Let him continue.

SHRI JAGMOHAN : The basic point, which I was making, was that unless we create a new concrete institutional frame-work which answers our special require-ments, we will not be able to do so. Our friends were saying that a lot of monev is being spent on Delhi. That is true in a way. But I would also like to remind you that this is the capital city and a lot of requirements arise because it is the capital city. They are not local requirements. Unfortunately, you see what happens to the New Delhi land. I will give you one example, say Barakhamba Road or Curzon Road. What happens ? Where there are multi-storeyed buildings, the unearned value of the land or the conversion charges are all covered by the Government of India, whereas the civic services have to be provided by the local body. If there is a multi-storeyed building, naturally, you have to augment water supply, electricity supply and sewers. All these burdens are on the local body, whereas the cream is taken by the Central Government. Our friends elsewhere said that Delhi is being pampered because \ a lot of money is being given. It is the other way round. Delhi's money is being taken away and it has to bear the burden and that is why the gap is increasing.

There are other points. If you have the patience, I have just two or three suggestions to make for the consideration of the Home Minister. One is with regard to property tax. There are six lakh property-owners in the city and they are being harassed bacause, *of* the variations in the property tax. Some courts have given judgements as the Municipal Committees have been doing all this. This has created a lot of problems and opened the avenues for corruption. In this Bill there is no amendment to section 169. I don't want to move an amendment because, I think, the hon. Minister would take care of the problem which I am pointing out without proposing any amendment. I would request him that they should have one concrete simple formula for determination of the property tax in Delhi. Whatever formula you want to evolve, fix the property tax for 10 years or 12 years. Due to rateable value every time a house owner is harassed by a notice, the house owner goes and files an objection and again he goes and files an objection and then he goes into litigation. It is so simple- Charge property tax on the basis of the cost of construction, the date of construction and the area on which the house is built. On that basis you fix the property tax so that everybody knows that he has to pay this much house tax every year and nothing more than that. He will not receive any notice- There will not be an army of small, petty, officials to pass orders, to do things like that. This is one aspect of property tax.

The other aspect is building by-laws are being violated with impunity everywhere- Make a test case in a few cases. The best thing to do is demolish a good building of a rich person. Then you will see that unauthorised constructions in Delhi will vanish. Today, unfortunately a gang has developed in Delhi which is breaking old houses and then building a number of dwelling units out of those houses and selling them in, advance to a group of architects, building contractors and moneyed people. Those

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

bouses are being sold for Rs. 40 lakhs or Rs. 50 lakhs. Whereas these people are making money under one pretext or the other by manipulation, the city is being choked with traffic because in place of one dwelling unit if you construct 10 dwelling units, you will choke the roads, you will choke the water supply and you will have no water supply at the tail end. Similarly, due to electricity fluctuation your transformer will not be able to work. Today we are building a city where we have got six T.V. channels but we have no electricity to view even one channel. I think this is the lopsided development against which I am speaking. Unless you have a real control over the urban land, you will not be able to stop this racketeering, you will not be able to give land to the poor people at subsidised rates, you will not be able to raise funds. For example, take the case of Nehru Place. Rupees eighteen crores were taken out of that land by developing and selling that land. Those Rs. 18 crores were used for subsidising the poor and for creating green lungs. So, that is the only way a poor country can develop cities. Our Minister went there. Naturally, if any unauthorised construction is done at the lower level, if there is no drainage, there will be water logging. He may pass 101 orders. But nobody will be able to correct that. This defect has arisen because people have constructed it in low lying areas, without development, without any sewerage plan. Therefore, it requires a very comprehensive study. I don't wish to stand in the way of this Bill. Let it go as it is because already many changes are overdue. But I suggest that with the passage of time an institutional framework has been suggested which could be considered by the Government of India. We could evolve a new city. We want to build a city which is the pride of India, which should be able to create a new commitment in the nation. You go to Paris. People take pride in Paris because it is a reflection of the French civilization. The amount of tourist traffic you are getting today, you have it despite the condition of Delhi. Therefore, the culture of the city which we should create in Delhi, the vision which we should have in Delhi will have an all India impact and the ripples of change from this place can go to other cities. Similarly, those cities should become more dynamic institutions of poverty alleviation, giving more employment. Unfortunately, due to this liberalisation and so on we are now going to have a city which will have 90 per cent of its people living in primitive conditions and 10 per cent in high technology with fax and so on. The pattern of this city will be 20 to 25 lakh cars in the city, the Yamuna polluted to the worst extent, the fourth largest worst pollutant city of the world and 350 gallons of sewage pumped into the Yamuna everyday. Which Government can clean that Yamuna ? If 300 million gallons of sewer water is to be released, if 250 million gallons of fresh water is to be got, it is impossible. Mr. Vice-Chairman, Sir, there are many other points. But I don't want to tax you because I understand that you are having the time constraint. So, I conclude now.

Thank you, Sir.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, यह दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (एमेन्डमेंट) बिल, 1993 लाया गया है । यह बिल देखने से यह पता लगता है कि इसमें जमूरियत की स्पिरिट कम है और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का जजबा इसमें बहुत ज्यादा है । आप शुरू से आखिर तक देखिये । इसमें 10 मेम्बर को नोमिनेट करने की बात कही गई है । इनको यहां के लेफ्टि० गवर्नर नोमिनेट करेंगे । जाहिर है कि जब लेफ्टि० गवर्नर 10 मेम्बर को काउंसिल में नोमिनेट करेंगे तो जिस पार्टी के लेफ्टि० गवर्नर होंगे उसमें पूरे के पूरे अपनी पार्टी के लेंगे । इससे जमूरियत की स्पिरिट खत्म हो जाती है । इसलिए मैं यह कहूँगा कि इन 10 मेम्बर्स को भी इलेक्शन से बनाया जाय और नोमिनेशन के लिए ऐसे सरयत रखे जाये कि लेफ्टि० गवर्नर पावन्द हो जाय कि उसके मुताबिक उनकी नोमिनेशन हो ।

दूसरी बात यह है कि मेयर के ताल्लुक से कहा गया है कि वह सिर्फ काउंसिल की मीटिंग को प्रेजाइड करेगा । इससे हट कर मेयर को कोई अख्तियारात नहीं दिये गये हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेयर को एक्जीक्यूटिव पावर्स दिये जाने चाहिएं । अगर मेयर को सिर्फ प्रेजाइडिंग के ही अख्तियारात होंगे तो ब्यूरोक्रेसी सब कुछ करेगी और इससे नौकरशाही का ताल्लुक ज्यादा बढ़ जाएगा । तीसरा एतराज मेरा यह है कि डिजोल्यूशन आफ कारपोरेशन के ताल्लुक से उसके लिए कोई रिजन्स होने चाहिएं । लेकिन इस बिल में रिजन्स नहीं बताये गये हैं कि किन हालात में कारपोरेशन को डिजौल्व किया जाएगा... (व्यवधान) । मैं आन्ध्र प्रदेश की एसेम्बली की बात या हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ । मुझे डिजोल्यूशन आफ कारपोरेशन के ताल्लुक से एतराज है । सबसे पहले तो कारपोरेशन को डिजोल्व नहीं होना चाहिए । एक दफा आप यह प्रोविजन रखेंगे तो इसका मिसयूज होगा और पोलिटिकली मोटिवेटेड इसमें आ जाएगा । इसलिए मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रोविजन को आप निकाल दें । अभी जैसा जगमोहन जी ने कहा कि इसमें प्रोपर्टी टैक्स और

बिल्डिंग बाई लाज की बात है वह सिर्फ दिल्ली के हद तक नहीं है बल्कि पूरे मुल्क ताल्लुक से इसको देखा जाना चाहिए । पूरे देश में जितनी भी बड़ी-बड़ी सीटीज हैं वे बढ़ती जा रही है । इसलिए प्रोपर्टी टैक्स और बिल्डिंग बाई लाज के लिए कोई एक फार्मुला बनाना चाहिए और उसी फार्मुले के तहत प्रोपर्टी टैक्स मुकर्रर किया जाय । दिल्ली में ही नही बल्कि हिन्दुस्तान में जितने भी बड़े-बड़े शहर है, मेट्रो-पोलिटन सीटिज है वहां पर इस फार्मुले को लागू किया जाना चाहिए । इसके अलावा शहरी हकुक के ताल्लुक से भी इसमें बहुत कम कहा गया है । पानी के ताल्लुक से, ड्रेनेज के ताल्लुक से, बिजली के ताल्लुक से, इसमें बहुत कम कहा गया है । तवक्कू यह की जा रही थी कि हमारे होम मिनिस्टर साहब इसमें जमूरियत की स्पिरिट को जोड़ते । जमूरियत को जोड़ने के बजाय नौकरशाही के ताल्लुक से इसमें ज्यादा कहा गया है । इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ।

श्री محمد خلیل الرحمٰن "آندھرا پردیش"

جناب وائس چیئرمین صاحب۔ یہ دلّی میونسپل کارپوریشن "امنڈمنٹ" بل ۱۹۹۳ لایا گیا ہے۔ یہ بل دیکھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں جمہوریت کی اسپرٹ کم ہے اور بیوروکریسی۔ نوکر شاہی کا جذبہ اس میں بہت زیادہ ہے۔ آپ شروع سے آخر تک دیکھئے۔ اس میں ۱۰ ممبر کو نامی نیٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ان کو یہاں لیفٹیننٹ گورنر نامی نیٹ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر ۱۰ ممبر کو کاؤنسل میں نامی نیٹ کریں گے تو جس پارٹی کے لیفٹیننٹ گورنر ہوں گے اس میں پوسے کے پوسے اپنی پارٹی کے لیں گے۔ اس سے جمہوریت کی اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے میں یہ کہوں گا کہ ان ۱۰ ممبرس کو بھی الیکشن سے بنایا جائے اور نامی نیشن کیلئے ایسے شرائط رکھے جائیں کہ لیفٹیننٹ گورنر پابند ہو جائے کہ اس کے مطابق انکی نامی نیشن ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ میئر کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ وہ صرف کاؤنسل کی میٹنگ کو پریزائڈ کریگا۔ اس سے ہٹ کر میئر کو کوئی اختیارات نہیں دیئے گئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میئر کو ایگزکٹو پاورس دیئے جانے چاہئیں۔ اگر میئر کو صرف پریزائڈنگ کے ہی اختیارات ہونگے تو بیوروکریسی سب کچھ کریگی اور اس سے نوکر شاہی کا تعلق زیادہ بڑھ جائے گا۔ تیسرا اعتراض میرا یہ ہے کہ ڈی زولیوشن آف کارپوریشن کے تعلق سے اسکے لئے کوئی ریجنس ہونے چاہئیں۔ لیکن اس بل میں ریجنس نہیں بتائے گئے ہیں کہ کن حالات میں کارپوریشن کو ڈی زالوو کیا جائے گا... مداخلت... میں آندھرا پردیش کی اسمبلی کی بات یا حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے ڈیزولیوشن آف کارپوریشن کے تعلق سے اعتراض ہے۔ سب سے پہلے تو کارپوریشن کو ڈی زالوو نہیں ہونا چاہیئے۔ ایک دفعہ آپ پرووزن رکھیں گے۔ تو اس کا مسیوز ہوگا اور پالیٹیکل موٹیویٹڈ اس میں آجائے گا۔ اس لئے میں آنریبل منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پرووزن

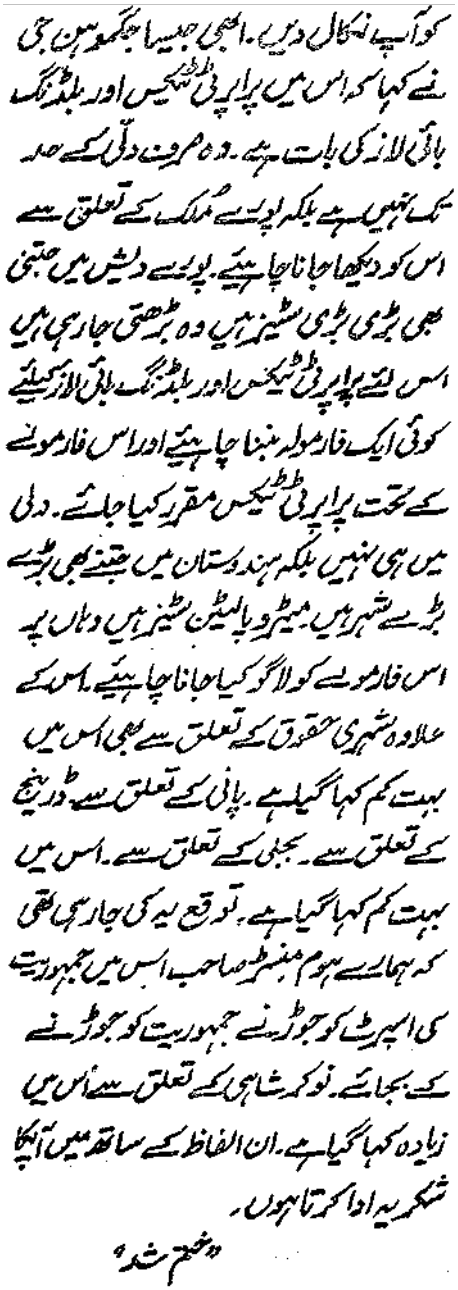

کو آپ نکال دیں۔ ابھی جیسا جگموہن جی نے کہا کہ اس میں پراپرٹی ٹیکس اور بلڈنگ بائی لاز کی بات ہے۔ وہ صرف دلی کے حد تک نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے تعلق سے اس کو دیکھا جانا چاہیئے۔ پورے دیش میں جتنی بھی بڑی بڑی سٹیز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اس لئے پراپرٹی ٹیکس اور بلڈنگ بائی لاز کیلئے کوئی ایک فارمولہ بننا چاہیئے اور اس فارمولے کے تحت پراپرٹی ٹیکس مقرر کیا جائے۔ دلی میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں۔ میٹروپالیٹن سٹیز ہیں وہاں پہ اس فارمولے کو لاگو کیا جانا چاہیئے۔ اس کے علاوہ شہری حقوق کے تعلق سے بھی اس میں بہت کم کہا گیا ہے۔ پانی کے تعلق سے ڈرینج کے تعلق سے۔ بجلی کے تعلق سے۔ اس میں بہت کم کہا گیا ہے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب اس میں جمہوریت کی اسپرٹ کو جوڑنے جمہوریت کو جوڑنے کے بجائے۔ نوکر شاہی کے تعلق سے اس میں زیادہ کہا گیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپکا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

"ختم شد"

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak. Though the time is short, I will try to put forth my views. Sir, the Balakrishnan Committee was appointed to study the structure of the civic body and the Committee has found that there different authorities resulting in contradictions.

Sir, a large majority of the citizens of Delhi are people living in slums and resettlement colonies. These are the people who are living in Jhuggis. The recent rains have brought to light the need for a clear and efficient drainage system which will not create any health hazards. In most of the slums and resettlement areas, poor people live with large families. In rainy season, water stagnates. The roads are horrible. In the New Delhi area at least you find some sort of clean roads. It is not so in other parts. Tha civic needs of the population have to be met properly.

In the resettlement colonies and in the slum areas, various diseases are spreading. There is garbage all around the Jhuggis, rain water is there, small ponds are there and mosquitoes breed there. Many people have lost their lives because of cholera and gastro-enteritis caused by the insanitary conditions in these areas. The per capita expenditure per year on these areas is only Rs. 15 while in the case of South Delhi, it is Rs. 92. I do not know why this discrimination, why this inequality should be there. How the administration is going to neutralise this imbalance, I do rot know. It is for the Minister to clarify this and make amends for this because it is these people who want the help of the Minister and the Government. It is strongly felt that the Delhi Municipal Corporation will do justice to the people if it can be divided into at least four . units which means divsion of localities within manageable limits and if attention is concentrated on the welfare of citizens. This will go a long way in decen-tralising the power and ensuring effrient functioing and providing civic. amenities to the people. *But t*here is no decentralisation in this Bill, as far as I can see. The Zonal Committee is there only on paper with no powers, and so, they are not effective in rendering real service to the people at large. Nothing .. seems to have been mentioned with regard to the resettlement colonies and there is no whisner at all about this. This needs to be clarified.

Sir, there is a strop at feeling that the Central Government will have a direct control over the Municipal Corporation. This feline should be removed Then, corruption is rampant in the Corporation as it exists today. For anything and everything people have to go to the Corporation and when they go to the offices

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

of the Corporation for their needs, they have to pay something. Otherwise, the papers will not move. How the Government is going to tackle the corrupt officials and the corrupt administration, it is for the Minister to explain. The Minister should try to find a way out to set things right.

Then, Sir, the increase in the number of Municipal Councillors is a welcome move. The Bill intends to increase by one-third the existing strength. There is a provision for nominating ten persons. This power should not be misused. It is likely to be misused by the party coming to power in the Municipal Corporation.

It has been said that DESU and the Water Supply Department would be given to other agencies. It is not known what those agencies are. What are those agencies ? This point needs clarification.

With these words, Sir, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, Mr. Minister to reply.

SHRI S. B. CHAVAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I must express my gratitude to all the hon. Members who have participated in the debate and given their valuable suggestions. I do not know whether I will have the time to specially react to some of the points which the hon. Members have made specially Mr. Inder Kumar Gujral and Mr. Jagmohan. Their ideas were in fact, very refreshing. And I quite agree with them that ultimately it is not the pattern which is ultimately going to decide the kind of institution that we would like to develop-in the city of Delhi. It is a sense of commitment and the way the whole thing is worked out. There is nothing wrong with the pattern. Both the patterns were available. And in India we have been following this pattern of having the Mayor, where he is the presiding authority of a deliberative body, and the decision taken by the Corporation becomes the responsibility of the Commissioner and the entire hierarchy of other officers to implement, whatever decisions have been taken by the Corporation. Our lady Member, Smt. Sarala Maheshwari, said, "I welcome the idea of one third of the members being women, but I do not understand what the woman Mayor can do in one year." She has to understand that every Mayor has to be for one year only. The first Mayor will be a women. In the third year, we are going to have a Scheduled Caste person. So, this is the system that we would like to develop. If they are dedicated-people, I am sure that in a period of one year, a number of things can be done. And at least you can pave the way for having certain things which you have in your mind to be implemented in the near future. Nobody can possibly say, "I will be able to contribute in such a manner that in my present term, I will be able to implement everything that I have in mind." So, you can lay down certain policies which ultimately you will be able to implement in due course.

Unfortunately, the Leader of the Opposition is not here. He had made certain points. That is the usual kind of song that he has. And that is about the kind of franchise which has been bestowed on the citizens of Delhi. He has to understand that this is a new kind of experiment that we are trying to have, giving State-hood, but at the same time this being a capital city, having some kind of control due to which a methodical and planned development of the city should be possible. It should be possible for us to prepare a perspective plan over a period of 15 years or 20 years, and after every five years, we should be able to find out as to how far we have been able to achieve what we had promised for the next 20 to 25 years. So, the kind of franchise is a kind of compromise that we had to have, and that is why he has to reconcile with that idea.

Sir, the other point which I am not able to understand is about the Ministry of Urban Development and also the CPWD. I have not been able to quite understand this. "At one time, you notified all the land under Section 4. And after 25 years, if you require, you apply Section 6 and pay them at the old rate." I have not been able to quite understand this. This is something preposterous. I don't think that it is obtaining anywhere in India, not only in Delhi. There are Supreme Court judgments. After the Supreme Court judgment, after three years, the notification that you have issued lapses. You have to issue a fresh notification if you want to acquire the land. But to say that for 25 or 30 years all the lands have been notified under Section 4 and they are being paid at very old rates is not correct.

Hon. Shri Sikander Bakht referred to the building bye-laws and other complaints. I am sure he understands the problem. We have purposely kept the building bye-laws with the Government of India. But the whole thing is ultimately going to be administered through the State Government and also the Corporation.

It is the corporation which will prepare the draft, ask for objections and with the comments of the corporation and the Commissioner, it will come to the Government of India through the Delhi Administration. This is the kind of procedure. I don't think that with the best of intentions, even the Government of India — if they have to directly try to administer—would be able to do it. It is physically impossible. We cannot do that. Ultimately it is the decentralised authority who are going to get all those powers. But they should properly utilise the same. That is the only point which I would like to emphasise.

Another point which was made was about the pollution in the city. I am in full agreement with the hon. Member. We will have to do a large number of things to see that the kind of situation that we found just a fortnight back should not be repeated, when there was accumulation of water. The entire traffic was jammed. Nobody could move. The people could not go to their offices in time. That kind of situation needs to be avoided. So, drainage—not only open drainage but also the underground drainage, the storm water drains—has to be improved so that when such very heavy rain fall is there, it should be possible for them to drain out the whole water.

One thing which I would like to emphasise here is, in fact the basic approach that we have taken in this Bill is to see that powers are not centralised. They are decentralised. All the ward committees which we are going to create should in fact, be having all the powers in that area. We have been able to indicate an amount of Rs. 1 crore. If the requirement is for more amount, certainly that can be considered. But the effort should be made to see how far you are prepared to decentralise your powers in favour of the ward committees out of what is being given to the corporation. You have to make the ward committees the real authorities with powers of implementation. Let them be in charge of implementation. And if that were to materialise, I am sure everybody in this House, including the Government, will be prepared to decentralise the authority and give more powers to decentralised authorities.

There are two points which the hon. Member, Shri Jagmohan made. This was about the property tax and the kind of harassment that the people have been undergoing. There is a High Court judgement because of which there was an expert committee which was appointed. That committee has submitted its report. It is with the Urban Development Ministry. They are considering it. But I fully agree with the hon. Member that the entire procedure needs to be simplified in such a manner that there should hardly be any scope for indulging in the kind of corruption that we find. The other point was about the building bye-laws being violated, and the kind of encroachments that we find in a number of areas. These are the problems being faced for the last so many years. Every • year, I am sorry to say, things are really getting out of control.

There are some areas for which new boards are going to be created. You will be surprised to know that here is the Delhi Electricity Supply undertaking whose accumulated losses are of the order of Rs. 2550 crores, and if you were to add the cash loss, it will be a huge amount of money.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra: Pradesh): DESU?

SHRI S. B. CHAVAN: Yes. You will be surprised to know that the generation station is next -door, and the transmission loss is 22 per cent. There is a loss of 22 per cent—transmission loss— from a generation station which is just next door and it Is something which indicates that a terrible theft is going on. People are taking electricity directly from the transmission lines and they are not paying for it.

These are the different kinds of reasons why it was thought necessary that we cannot allow this kind of situation any loner and we will have to create a new authority. If it is the electricity board and if they are able to improve the situation, there is nothing like that.

Certainly, we will have such an electricity board, but whichever is the authority, it should be able to eliminate this kind of inefficiency. It is the height of inefficiency. For other reasons, I can understand. But 22 per cent transmission loss for a generating station which is next door is something which I am not able to reconcile with. That is why it has to be taken away.

Similarly, the water requirement of the city of Delhi is still a matter which is dependent on a number of State Governments, the neighbouring States. We will have to have a permanent water supply scheme. In regard to procurement of water, treatment of water and distribution of water, there will have to be the same kind of agency. That is the idea that we have. We would like to see that things improve and efficiency improves.

Some new kind of an atmosphere, some new work culture, we will have to develop in the city of Delhi. Unfortunately, I am sorry to say that with the kind of culture that I find, with the kind of indiscipline that I find, 1 do not think, in the near future, there is a possibility of things showing tremendous improvement. For satisfying Members, I can say anything. But in my heart Of hearts, I am not quite sure whether we are going to see things changing tremendously. I would be the happiest person if a new kind of work culture can be brought about in Delhi so that people are law-abiding they observe discipline, and are prepared to honour all the laws and by-laws which are made by their elected representatives. But I can see more is being violated than is being honoured by the citizens of Delhi. Everybody is having his own share in *the* kind of undesirable activities. I would not say the people are indulging themselves in corruption. This is the thing I wanted to emphasise.

Mr. Vice-Chairman, I have taken more of your time. I once again express my gratitude to all the hon. Members.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Sir, with your permission, I would like to seek one clarification from the hon. Minister. I would invite his attention to page 8 of the Bill. In the new section which is to be substituted for existing section 32, there is a provision where the councillor is being penalised. If a councillor dees cot take the oath within the prescribed time, he has to pay a penalty of Rs. 300. Is it not a thing which should be ensured by the person concerned, bv 'he officer concerned? He has to take the oath within a month. If he does not take tha oath within a month, he loses h s seat or he has to pay a penalty of Rs. 300. Why should he be penalised? Even a nominated representative has to pay the penalty.

SHRI S. B. CHAVAN: The hon. Mem-bar would be able to understand the significance of a person rot taking the oath when he sees wh?t happens if, as an elected Member of either this. House or the Lok Sabha, a person does not take the oath under the Constitution. I need not tell him. It is already there in the Constitution.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : I am not referring to it from that angle.

SHRI S. B. CHAVAN: I will look into that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, the question is :

> That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, as passed by the Lok Sabha be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall now take up clausc-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 So 136 *were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, I beg to move :

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall now take up further discussion on the background Note on Review of Drug Policy.

MOTION RE. BACKGROUND NOTE ON REVIEW OF DRUG POLICY, 1986—Contd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FERTILISERS AND CHEMICALS (SHRI EDUARDO FAIERO) : Mr. Vice-Chairman, Sir, may I, at the outset, thank the Chairman and all the Members for having found time to discuss this policy?

Sir, the Background Note was laid on the Table of the House about a year ago; to be precise, on the 12th of the same month, i.e. August, last year. We have been delaying the formulation of the drug policy and its implementation looking forward to the debate in this House and looking forward to the wisdom of Members of both this and the other House.

So. this has created some criticism, and a point has been raised that the policy is the prerogative of the Government. That was how the criticism went. There was no need for us to evade a discussion in Parliament. We could have gone ahead, formulated a policy and implemented it, and then Parliament, as and when it thought fit, could have debated it in different forms of debates, questions and so on. But then we thourght otherwise. We thought that here we have an industry which is not an industry like any other industry. Here